देश का Darpan News TV
FASTWAY
airtel
Comming Soon
काम करने के लिए सम्पर्क करें

दैनिक समाचार पत्र

देश का दर्पण न्यूज

राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली व महाराष्ट्र से प्रकाशित

अब आपके मोबाइल पर डिजिटिल अख़बार
प्रदेश के ताजा समाचार
अपने लेख एवं समचार भेंजे
सम्पादक : उमेन्द्र राजपूत
7014997449, 9636058201
Email : deshkadarpannews@gmail.com
web.: www.deshkadarpannews.co

वर्ष-4, अंक-218 | जयपुर, गुरुवार, 04 जून, 2026 | मूल्य : 5.00 पेज:

टीएमसी में बड़ी टूट: बागी गुट ने ऋतब्रत को चुना नेता

ऋतब्रत बनर्जी को विधायक दल का नेता चुना, स्पीकर ने मंजूरी भी दी, ममता दीदी को मुख्य सलाहकार पद का प्रस्ताव

कोलकाता/एजेंसी
पश्चिम बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रहे सत्ता संघर्ष के बीच बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। पार्टी से निष्कासित विधायक ऋतब्रत बंद्योपाध्याय को विधानसभा में विपक्ष का नेता की मान्यता दे दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बसु की स्वीकृति के बाद नेता प्रतिपक्ष के लिए निर्धारित कक्ष भी खोल दिया गया और उसकी चाबी ऋतब्रत को सौंप दी गई। ऋतब्रत बंद्योपाध्याय ने दावा किया कि तृणमूल के टिकट पर निर्वाचित दो-तिहाई विधायक उनके साथ हैं और यही समूह अब विधानसभा में तृणमूल के संसदीय दल का बहुमत रखता है। उन्होंने कहा कि उनकी अगुवाई में विपक्ष भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के खिलाफ मजबूती से अपनी भूमिका निभाएगा। ऋतब्रत के अनुसार, तृणमूल के 80 विधायकों में से 60 विधायक उन्हें विपक्ष का नेता बनाए जाने के प्रस्ताव का समर्थन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल 58 विधायकों का लिखित समर्थन उनके पास है, जबकि दो अन्य विधायक राज्य से बाहर हैं और उन्होंने भी सहमति दे दी है। उनके समर्थन पत्र मिलते ही यह संख्या 60 हो जाएगी। नई टीम की घोषणा करते हुए ऋतब्रत ने बताया कि विधानसभा में आखरुज्जामान को मुख्य सचेतक बनाया गया है। वहीं, जावेद अहमद खान, सबीना यासमीन, शिउली साहा और संदीपन साहा को उपनेता नियुक्त किया गया है। इन सभी के समर्थन संबंधी पत्र विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिए गए हैं। ऋतब्रत ने कहा कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा नवान्न में बुलाई गई प्रशासनिक समीक्षा बैठक में विपक्षी विधायकों को भी आमंत्रित किया गया था, जिसके लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया।

कोलकाता, हावड़ा और उत्तर 24 परगना के विपक्षी विधायक बैठक में शामिल हुए

कोलकाता, हावड़ा और उत्तर 24 परगना के विपक्षी विधायक बैठक में शामिल हुए और विपक्ष सरकार के सकारात्मक कदमों का समर्थन करने के साथ-साथ जनहित के मुद्दों पर सशक्त तरीके से आवाज उठाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि वह व्यक्तिगत नेतृत्व की राजनीति में विश्वास नहीं करते और सभी निर्णय सामूहिक चर्चा के आधार पर लिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने तृणमूल प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से संसदीय दल के सलाहकार की भूमिका निभाने का अनुरोध करने की बात कही। ऋतब्रत ने यह भी स्पष्ट किया कि उनके समूह का अभिषेक बनर्जी से कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। गौरतलब है कि, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर विवाद उस समय शुरू हुआ था, जब वरिष्ठ विधायक शोभनदेव को विपक्ष का नेता बनाने संबंधी प्रस्ताव सामने आया। इसके बाद आरोप लगा कि इस प्रस्ताव के समर्थन में कई विधायकों के हस्ताक्षर जाली तरीके से इस्तेमाल किए गए हैं।

हस्ताक्षर जालसाजी का मामला विधानसभा प्रशासन के संज्ञान में

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पहले दावा किया था कि ऋतब्रत बंद्योपाध्याय और संदीपन साहा ने ही कथित हस्ताक्षर जालसाजी का मामला विधानसभा प्रशासन के संज्ञान में लाया था। इसके बाद हेयर स्ट्रीट थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई और मामले की जांच सीआईडी को सौंपी गई। जांच एजेंसी अब तक 13 विधायकों से पूछताछ कर चुकी है। इस बीच, तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव व लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर हाल के संसदीय उदाहरणों का हवाला देते हुए शोभनदेव चट्टोपाध्याय को ही विपक्ष का नेता मान्यता देने की मांग की थी। बुधवार को एक ओर जहां ऋतब्रत बंद्योपाध्याय विधानसभा में अपने नेतृत्व वाले समूह की ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे।

ममता बनर्जी सलाहकार के रूप में मार्गदर्शन दें: ऋतब्रत

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी संघर्ष के बीच नवमान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता ऋतब्रत बंद्योपाध्याय ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी का उनकी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, जबकि ममता बनर्जी को वह एक वरिष्ठ नेता के रूप में पार्टी की मुख्य सलाहकार की भूमिका में देखना चाहते हैं। बुधवार को विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता मिलने के बाद पत्रकारों से बातचीत में ऋतब्रत ने कहा कि अभिषेक बनर्जी की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उनके साथ हमारी पार्टी का कोई संबंध नहीं है। जनता के साथ भी उनका कोई जुड़ाव नहीं है। यदि ऐसा होता तो चुनावी हार के बाद वह 26 दिनों तक सार्वजनिक रूप से गायब नहीं रहते, बल्कि लोगों के बीच आते। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के बाद हुई घटनाओं के दौरान अभिषेक बनर्जी जनता के समर्थन का दावा करते रहे, लेकिन बाद में अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखना पड़ा।

समूह अभिषेक बनर्जी को लेकर किसी प्रकार की चर्चा करना नहीं चाहता: ऋत

ऋतब्रत ने कहा कि उनका समूह अभिषेक बनर्जी को लेकर किसी प्रकार की चर्चा करना नहीं चाहता और पार्टी की राजनीति को उनके प्रभाव से अलग रखना चाहता है। इसके विपरीत, ऋतब्रत ने तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी के प्रति सम्मान जताते हुए कहा कि वह राज्य और देश की एक वरिष्ठ राजनीतिक नेता हैं। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि ममता बनर्जी का लंबा राजनीतिक अनुभव है। हमारी इच्छा है कि वह पार्टी की मुख्य सलाहकार के रूप में मार्गदर्शन देती रहें और संगठन को दिशा प्रदान करें। ऋतब्रत की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब पश्चिम बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर खुला संघर्ष सामने आ चुका है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतब्रत बंद्योपाध्याय को विपक्ष का नेता मान्यता दिए जाने के बाद पार्टी के भीतर दो स्पष्ट धड़े दिखाई दे रहे हैं। ऋतब्रत का यह बयान तृणमूल कांग्रेस के भीतर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की भूमिकाओं को अलग-अलग परिभाषित करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

आदिवासी समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने पर ही होगा विकसित भारत का लक्ष्य : राष्ट्रपति

नई दिल्ली/एजेंसी
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बुधवार को एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरणों (आईटीडीए) और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं (आईटीडीपी) के राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब आदिवासी समुदाय भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ सके। आदिवासी समाज सांस्कृतिक रूप से अत्यंत समृद्ध है लेकिन योजनाओं की जानकारी और उनतक समय पर लाभ नहीं पहुंच पाते। आदिवासी परिवार आत्मसम्मान के साथ जीवन जीते हैं और उनके कल्याण के लिए योजनाओं को बार-बार उनके दरवाजे तक ले जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरणों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम, राज्यमंत्री दुगार्दास उइके, मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

राष्ट्रपति ने कहा कि यह सम्मेलन जनजातीय परिवर्तन कारकों का सम्मेलन है। आप सब पर यह जिम्मेदारी है कि जनजातीय समुदाय के कल्याण और विकास कार्यक्रमों को उनके गांव और घर तक पहुंचाएं। ऐसा करने से जनजातीय समुदाय के भाई-बहनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। राज्य और परियोजना स्तर पर काम करने वाले सभी लोग जब एक बड़े उद्देश्य के साथ विचार-विमर्श करेंगे तो अनेक उपयोगी समाधान सामने आएंगे।

उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय के गांव और बस्तियां दूरदराज के इलाकों में जंगलों और पहाड़ों में स्थित हैं। ऐसे क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना अधिकारियों का कर्तव्य है। प्रधानमंत्री जन योजना के तहत 20,000 से अधिक आदिवासी गांवों तक विकास कार्यक्रम पहुंचाने का लक्ष्य है। विशेष रूप से पीबीटीजी समूहों को घर, जमीन और आजीविका उपलब्ध कराना आवश्यक है।

दिल्ली: मालवीय नगर के रेस्तरां में आग का तांडव, 21 लोगों की हुई मौत

नई दिल्ली/एजेंसी
दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में बुधवार सुबह फ्लोरिश स्टे बीएंडबी रेस्टोरेंट में लगी आग में 21 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं इस घटना में 40 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। दमकल की आठ गाड़ियों ने पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया है। इलाके में भीषण आग के बाद घंटों तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। आग इतनी तेजी से फैली कि रेस्टोरेंट और उससे जुड़े हिस्सों में मौजूद कई लोग अंदर फंस गए। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग, दिल्ली पुलिस और आपदा प्रबंधन एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंचीं और बड़े स्तर पर राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस दुखद घटना में 21 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। 8 दमकल गाड़ियों की सहायता से आग को सफलतापूर्वक बुझा दिया गया है। पुलिस, अग्निशमन सेवाओं और अन्य आपातकालीन बचाव कर्मियों के समन्वित प्रयासों से, 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है और चिकित्सा उपचार के लिए पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अभी तक यह संख्या उन सभी लोगों की है, जिन्हें इमारत से निकाला गया है। इनमें से कितने लोग घायल हैं और उनकी स्थिति क्या है, इसकी विस्तृत जानकारी संबंधित अस्पतालों से जुटाई जा रही है।

प्रशासन लगातार अस्पतालों के संपर्क में है

प्रशासन लगातार अस्पतालों के संपर्क में है और घायलों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। राहत एवं बचाव अभियान के दौरान दमकल विभाग के जवानों को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आग बुझाने और अंदर फंसे लोगों को निकालने के दौरान एलएफएम योगेंद्र घायल हो गए। उन्हें तत्काल प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया गया। वहीं एसटीओ मनोज की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें ड्यूटी से हटाकर वापस स्टेशन भेजा गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए अग्निशमन विभाग के प्रधान निदेशक भी मौके पर पहुंच गए। वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में पूरे अभियान की निगरानी की जा रही है। अग्निशमन विभाग, पुलिस और अन्य एजेंसियों की संयुक्त टीम इमारत के हर हिस्से की गहन तलाशी ले रही हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई व्यक्ति अंदर फंसा न रह गया हो। मौके पर मौजूद अधिकारियों के अनुसार आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन धुआं और गर्मी के कारण सर्च ऑपरेशन बेहद सावधानी से चलाया जा रहा है। बचाव टीमें इमारत के अंदर प्रवेश कर हर कमरे और बेसमेंट की जांच कर रही हैं।

आरबीआई ने कहा-सोना बेचने की खबरें गलत, भंडार 880.52 टन पर स्थिर

नई दिल्ली/एजेंसी
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने बुधवार को उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया है, जिनमें यह दावा किया गया था कि उसने अपने स्वर्ण भंडार का कुछ हिस्सा बेच दिया है। आरबीआई ने स्पष्ट किया कि उसके पास मौजूद सोने की मात्रा 880.52 टन पर अपरिवर्तित बनी हुई है। एक अमेरिकी मीडिया कंपनी ब्लूमबर्ग ने दावा किया था कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रभाव से विदेशी मुद्रा भंडार की रक्षा के लिए केंद्रीय बैंक ने लगभग 12 अरब डॉलर मूल्य का सोना बेच दिया हो सकता है। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स ने एक विश्लेषण आधार पर यह दावा किया था। केंद्रीय बैंक ने अफवाहों से बचने और प्रामाणिक जानकारी के लिए हमेशा आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की अपील की है। शीर्ष बैंक ने जारी बयान में कहा कि आरबीआई के संज्ञान में मीडिया के कुछ वर्गों में ऐसी रिपोर्टें आई हैं, जिनमें रिजर्व बैंक द्वारा सोना बेचे जाने की बात कही गई है।

आरबीआई इस बात पर जोर देता है कि ये रिपोर्टें सही नहीं हैं। आरबीआई ने कहा कि अपने मासिल बुलेटिन में वे सोने के भंडार की जानकारी देता है।

केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने 'नवाचार मंत्र' पहल शुरू की

नई दिल्ली/एजेंसी
केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी ने उद्देश्य टियर-2, टियर-3 शहरों और ग्रामीण इलाकों से आने वाले नवाचारों और उद्यमियों को सहयोग देने के लिए बुधवार को आईआईटी दिल्ली में नवाचार मंत्र राष्ट्रीय पहल का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया को केवल भारत में बने उत्पाद ही नहीं बल्कि भारत में कल्पित तकनीकों का भी उपयोग करना चाहिए, यही नवाचार मंत्र की सच्ची भावना है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने बताया कि इस पहल को राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबड) लागू करेगा और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर (एफआईटीटी), आईआईटी दिल्ली तकनीकी ज्ञान भागीदार होगा। कार्यक्रम में नीति-निमार्ताओं, स्टार्टअप इकोसिस्टम नेताओं, शिक्षाविदों, निवेशकों और युवा उद्यमियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में स्कैनएक्स्ट साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज के संस्थापक राजत वर्धन ने संचालन किया।

एनसीआर में पुराने ट्रक-बस बदलने की 9,585 करोड़ की योजना को मंजूरी

नई दिल्ली/एजेंसी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली-एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए 9,585 करोड़ रुपये की दो वर्षीय योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) को सहयोग दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य वायु प्रदूषण कम करना और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में पत्रकारों को बताया कि इस योजना को आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के तहत एनसीआरपीबी द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। इसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारें भी भागीदार होंगी।

योजना के तहत केंद्र सरकार 5,041 करोड़ रुपये देगी और राज्यों द्वारा लगभग 1,601 करोड़ रुपये कर रियायतों के रूप में दिए जाएंगे। योजना का लाभ दिल्ली-एनसीआर में पंजीकृत बीएस-क्ष या उससे पुराने मानक वाले ट्रक और बस मालिकों को मिलेगा, जिन्हें बीएस-श्क या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण गंभीर चुनौती बना हुआ है।

लाओस के विदेश मंत्री ने की राष्ट्रपति से मुलाकात

नई दिल्ली। लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंगसावन फोमविहाने ने बुधवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की। भारत की अपनी पहली यात्रा पर आए फोमविहाने का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं, जो बौद्ध धर्म और रामायण की हमारी साझा विरासत से प्रतिबिंबित होते हैं। इस वर्ष, हम लोग दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण सोपान है। राष्ट्रपति ने उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान से जुड़े शिखर सम्मेलनों में भाग लेने के लिए अक्टूबर 2024 में लाओ जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य की यात्रा पर गए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की परिभाषा तय करने के लिए उच्चस्तरीय कमेटी गठित की

नई दिल्ली/एजेंसी
उच्चतम न्यायालय ने अरावली पर्वतमाला की परिभाषा तय करने के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है। कोर्ट ने उच्चस्तरीय समिति से 31 अगस्त तक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

आईसीएफआरई के महानिदेशकर कंचन देवी करेंगी। कंचन देवी के अलावा इस कमेटी में भारतीय वन सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक डॉ सुभाष आशुतोष, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के पूर्व निदेशक डॉ राजेंद्र कुमार शर्मा, पर्यावरण मंत्रालय के पूर्व संयुक्त सचिव बृज मोहन सिंह राठौर और दिल्ली यूनिवर्सिटी के वनस्पति विज्ञान विभाग के पूर्व अध्यक्ष अशोक भटनागर शामिल होंगे। कोर्ट ने इस समिति की मदद करने के लिए दो विशेषज्ञों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रुप में नियुक्त करने का आदेश दिया। विशेष आमंत्रितों में इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स, बेंगलुरु के प्रोफेसर जगदीश कृष्णास्वामी और हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लक्ष्मीकांत शर्मा को नियुक्त किया है। कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय को निर्देश दिया कि वो इस कमेटी का सदस्य सचिव के लिए अपने मंत्रालय से निदेशक स्तर के किसी अधिकारी को नामित करें।

26 फरवरी को उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि वो विशेषज्ञों की राय लेगी कि क्या अरावली इलाके में खनन की इजाजत दी जा सकती है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से विशेषज्ञों का नाम सुझाने को कहा था। कोर्ट ने कहा था कि वो विशेषज्ञों से पूछेगी कि अगर अरावली इलाके में खनन की इजाजत दी जा सकती है तो किस हद तक। साथ ही इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा। कोर्ट ने मामले में पेश वकीलों से भी कहा था कि वे कमेटी बनाने के लिए विशेषज्ञों का नाम सुझाएं। कोर्ट विशेषज्ञों की राय का पूरी तरह आकलन करेगा, जिसमें अरावली हिल्स और अरावली रेंज की परिभाषा, सौ मीटर की ऊंचाई की सीमा का असर शामिल होगा।

प्रधानमंत्री के सम्मान में भाजपा की विराट जन आक्रोश सभा, कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जताया विरोध

वाराणसी। भारतीय जनता पार्टी महानगर एवं जिला इकाई की ओर से बुधवार को कचहरी स्थित जिला मुख्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस नेताओं द्वारा की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के विरोध में विराट जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल की अध्यक्षता में आयोजित सभा में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकताओं, पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया।

सभा के दौरान कार्यकताओं ने प्रधानमंत्री के समर्थन में तथा कांग्रेस नेतृत्व के विरोध में जोरदार नारेबाजी की। जिला मुख्यालय परिसर "प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान", "भारत माता की जय", "वंदे मातरम्" और "हर-हर महादेव" के नारों से गूंज उठा। कार्यकर्ता अपने हाथों में विभिन्न नारों और संदेशों वाली तख्तियां लेकर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया।

सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय द्वारा प्रधानमंत्री के विरुद्ध की गई टिप्पणियां लोकतांत्रिक मयार्दाओं के अनुरूप नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सकारात्मक राजनीति के बजाय व्यक्तिगत आरोपों और विवादित बयानों का सहारा ले रही है। वक्ताओं ने कहा कि देश की जनता इस प्रकार की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगी।

भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक स्तर पर नई पहचान बना रहा है और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष जनसमर्थन के अभाव में इस तरह के बयान देकर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहा है।

कार्यक्रम में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविंद्र जायसवाल, दयाशंकर मिश्र ह्यदयालुह्ल, महापौर अशोक तिवारी, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, नीलकंठ तिवारी सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सभा के समापन पर भाजपा पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराया तथा कार्यकताओं ने जनजागरण अभियान चलाने का संकल्प लिया।

बठिंडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 258 ग्राम हेरोइन, देसी रिवॉल्वर व 19 जिंदा कारतूस बरामद, चार आरोपी गिरफ्तार

बठिंडा, 3 जून (सुरेश रहेजा, परवीन कुमार, साहिल रहेजा)।पंजाब पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) **गौरव यादव, आईपीएस* तथा *डीआईजी बठिंडा रेंज हरजीत सिंह, आईपीएस* के दिशा-निदेर्शों के तहत नशों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत बठिंडा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 258 ग्राम हेरोइन (चिट्टा), एक कार, एक देसी रिवॉल्वर तथा 19 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।

वरिष्ठ पुलिस कप्तान (एसएसपी) डॉ. ज्योति यादव, आईपीएस के नेतृत्व तथा *डीएसपी रामपुरा फूल मनोज कुमार, पीपीएस* की अगुवाई में थाना फूल पुलिस ने यह कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार थाना फूल में मुकदमा नंबर 75 दिनांक 1 जून 2026 को एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया गया था।

रेजिडेंशियल जगह पर चल रहा है कमर्शियल एक्टिविटीज नगर निगम रोकने में नाकाम राजस्थान मंत्री जबर सिंह खर्रा को शिकायत करने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

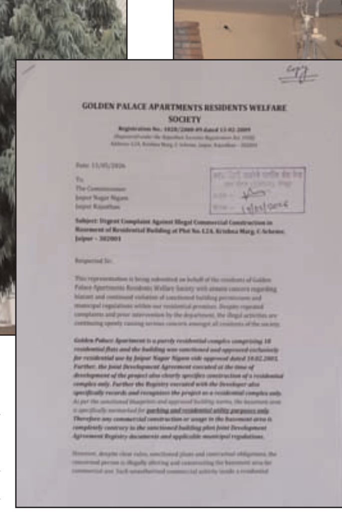

इन दिनों नगर निगम की लापरवाही से जयपुर में अवैध अतिक्रमण जोड़ों पर है जयपुर के हर क्षेत्र में लगभग अवैध अतिक्रमण किए जा रहे हैं शिकायत के बाद भी कुछ भ्रष्ट अधिकारी के सहयोग से जयपुर में हर जगह अवैध अतिक्रमण हो रहा है, ऐसा ही एक मामला जयपुर के सी स्कीम स्थित गोल्डन प्लेस अपार्टमेंट्स का है जिसमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर कमर्शियल काम किया जा रहा है नीचे बहुत सारे ऑफिस बनाकर संचालित किया जा रहा है जिसमें आने वाले बहुत सारे कर्मचारी से इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग परेशान है उनका कहना है की हम सभी जो इस अपार्टमेंट में रहते हैं उनकी संख्या जितनी है उससे दोगुनी संख्या इन ऑफिस में काम करने वाले लोगों की है जिस कारण महिलाएं बाहर निकलने में सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है जो पीने का पानी या नहाने का पानी मिलता है पहले भी पर्याप्त नहीं था लेकिन इन ऑफिस को खुलने के बाद आने वाले लोग इतने हो जाते हैं कि हम सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ता जबकि इस जमीन को फ्लैट बनाने वाले प्रमोटर ने कागज में पार्किंग दिखाया है उसके बावजूद इस पार्किंग के जगह को तोड़कर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है ऑफिस बनाए जा रहे हैं और जो नीचे पिलर दिया हुआ है उसमें भी तोड़फोड़ किया जा रहा है इस प्रकार से हम लोगों की बिल्डिंग गिर भी सकती है नुकसान भी हो सकता है हमने इसकी शिकायत मंत्री जबर सिंह खारा को किया था नगर निगम के अधिकारी को भी किया था लेकिन कोई हमारी नहीं सुन रहा हम जाए तो जाए कहां हमारे बच्चे और बच्चियों की बचपन इन लोगों ने छीन लिया है

नमोघाट पर युवा शक्ति ने जगाई पर्यावरण संरक्षण की अलख, प्लास्टिक का उपयोग बंद करने का संदेश

वाराणसी।
उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में नमामि गंगे के स्वयंसेवकों ने बुधवार को नमो घाट पर युवाओं के साथ पर्यावरण संरक्षण की अलख जगाई। अपनी ऊर्जा और नवीन सोच के माध्यम से युवा पीढ़ी जलवायु परिवर्तन से लड़ने और एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने में आगे बढ़े, ऐसी अपील करते हुए पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन भागीदारी सुनिश्चित करने का आवाह्न किया गया। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता प्रदर्शित करती तख्तियों के साथ नमो घाट पर जन सामान्य को स्वच्छता का संकल्प दिलाया गया। कार्यक्रम में शामिल गंगा सेवी राजेश शुक्ला ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। युवा जमीनी स्तर पर व सोशल मीडिया का उपयोग करके जलवायु संकट और पर्यावरण बचाव के संदेशों को तेजी से जन-जन तक पहुंचा सकते हैं। वे वृक्षारोपण अभियानों, स्वच्छता कार्यों और अपशिष्ट प्रबंधन में सक्रिय रूप से नेतृत्व करें तो सतत जीवनशैली आगे बढ़ती रहेगी। उन्होंने कहा कि दैनिक जीवन में प्लास्टिक का उपयोग बंद करना, जल और ऊर्जा बचाना इसके प्रमुख उदाहरण हैं। युवाओं को संदेश दिया कि आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम न केवल खुद पर्यावरण के प्रति जागरूक रहेंगे, बल्कि अपने समाज और देश को भी जागरूक करेंगे। हमारा आज का छोटा सा कदम, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ कल का निर्माण करेगा। जागरूकता अभियान में अमन, सरोज, शिवानी, अंजलि, कोमल, अंशिका, शालिनी आदि ने भागीदारी की।

लखनऊ की दो अलग-अलग मार्ग दुर्घटनाओं में दो लोगों की मौत

लखनऊ।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलग-अलग थाना क्षेत्र में हुए मार्ग दुर्घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

दुबग्गा थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह हरदोई रोड स्थित शिफा हॉस्पिटल के सामने एक ट्रक और मोटर साइकिल की टक्कर हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की। दुर्घटना में घायल ट्रक गोण्डा जिले के तबेपुर निवासी अमृतलाल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। प्रयागराज के महारजपुर निवासी विपुल कुमार द्विवेदी घायल हैं। विपुल का इलाज केजीएमयू लखनऊ में चल रहा है। पुलिस ने घटना की जानकारी परिवार को देते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

इसी तरह तालकटोरा थाना क्षेत्र में मंगलवार की रात पं. दीन दयाल उपाध्याय डिग्री कॉलेज के पास, ई-ब्लॉक, राजाजीपुरम में एक तेज रफ्तार डीसीएम ने सड़क पर पैदल जा रहे एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। इससे वह व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई।

सूचना प्राप्त होते ही प्रभारी निरीक्षक पुलिस बल के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और आवश्यक जानकारी एवं साक्ष्य संकलित किया। पुलिस ने मृतक की पहचान गोण्डा जिले के ग्राम कुमेदानी निवासी सुभाष कनौजिया उर्फ मिन्कू (22) के रूप में की। वह वर्तमान में हैदर कैनाल, पं० दीन दयाल उपाध्याय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, ई-ब्लॉक, राजाजीपुरम के पास झुग्गी-झोपड़ी बनाकर रहता था।

वाराणसी में दो सौ साल पुरानी अजगैब शहीद मस्जिद पर चला बुलडोजर

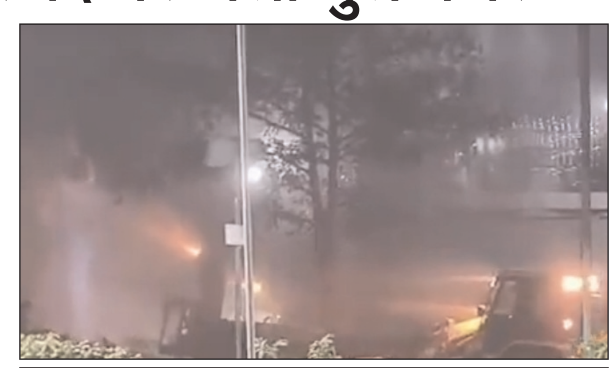

वाराणसी।
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में राजघाट क्षेत्र में दो सौ साल पुरानी अजगैब शहीद मस्जिद को मंगलवार की आधी रात को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया गया। बुधवार की सुबह वहां पहुंचे लोगों को मस्जिद के स्थान पर मलबा देखने को मिला। मस्जिद के स्थान को साफ कराकर नये मॉडल स्टेशन के लिए उपयोग किया जाएगा।

पुलिस उपायुक्त काशी जोन गौरव बंसवाल ने कहा कि अजगैब शहीद मस्जिद के चारों तरफ बेरिकेडिंग कराया गया था और एहतियात के रूप में पीएसी और पुलिसकर्मियों को भी लगाया गया था। रेलवे प्रशासन की ओर से पांच बुलडोजर मंगवाए गए। इसके बाद करीब 42 फीट ऊंची मस्जिद को ढहा दिया गया। अभी मलबा हटाने का काम हो रहा है, अभी भी पुलिस और पीएसी के करीब एक हजार जवान तैनात है। इस दौरान एडीसीपी वैभव बांगर, एसीपी विजय प्रताप भी मौजूद रहे।

देवरिया में लापरवाही पर लेखपाल निलंबित, दो अन्य के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई शुरू

देवरिया।
उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के सलेमपुर तहसील प्रशासन ने शासन के प्राथमिकता वाले कार्यों में लापरवाही और अनुशासनहीनता को गंभीरता से लेते हुए राजस्व विभाग के कर्मचारियों पर कार्रवाई की है। राजस्व निरीक्षक क्षेत्र भटनी में तैनात लेखपाल समीर सिद्धार्थ को निलंबित कर दिया गया है, जबकि लेखपाल धीरेन्द्र कुमार और शशिकांत यादव के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। एसडीएम दिशा श्रीवास्तव ने बुधवार को बताया कि 26 मई को तहसील सभागार में आयोजित फार्मर रजिस्ट्री एवं अंश निर्धारण कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान तहसीलदार ने लेखपाल समीर सिद्धार्थ को अपने क्षेत्र में जाकर फार्मर रजिस्ट्री का कार्य करने का निर्देश दिया था। आरोप है कि उन्होंने निदेर्शों का पालन करने से इनकार कर दिया और अधिकारियों से बहस की। मामले की जानकारी मिलने पर तहसीलदार से रिपोर्ट मांगी गई थी ।

उन्होंने बताया कि तहसीलदार की जांच रिपोर्ट में समीर सिद्धार्थ पर राजस्व कार्यों में लापरवाही, अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना, अनुशासनहीनता तथा शासकीय दायित्वों के प्रति उदासीनता के आरोप लगाए गए। रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उन्हें रजिस्ट्रार कानूनगो (भू-लेख) कार्यालय सलेमपुर से संबद्ध किया गया है, जहां उन्हें प्रतिदिन अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। उन्होंने बताया कि लेखपाल धीरेन्द्र कुमार और शशिकांत यादव के खिलाफ क्षेत्र में निवास न करने, शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने और उच्चाधिकारियों के निदेर्शों की अनदेखी करने की शिकायतें मिली थीं।

प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने पर दोनों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की संस्तुति करते हुए जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया है। मामले की विस्तृत जांच तहसीलदार अलका सिंह को सौंपी गई है।

एसडीएम दिशा श्रीवास्तव ने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाले कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ करना होगा। उन्होंने बताया कि शिकायतों और जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की गई है तथा जांच पूरी होने के बाद आवश्यकतानुसार आगे की कार्रवाई भी की जाएगी।

'गवर्नर' की कहानी पर 5 साल तक चला शोध, विपुल शाह ने शुरूआत से ही मनोज बाजपेयी को माना था पहली पसंद

जित मुंबईः मनोज बाजपेयी और अदा शर्मा स्टारर फिल्म 'गवर्नर' को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। भारत के 1991 के आर्थिक संकट और उस दौर के अनसुने नायकों की कहानी को पर्दे पर लाने वाली इस फिल्म की शुरूआत एक दिलचस्प आइडिया से हुई थी। लेखक सुवेंदु भट्टाचार्य ने इस विषय को सबसे पहले सनशाइन पिक्चर्स के सामने रखा था। भारत के आर्थिक इतिहास के इस महत्वपूर्ण लेकिन कम चर्चित अध्याय ने निमार्ता विपुल अमृतलाल शाह को तुरंत प्रभावित किया और उन्होंने इसमें एक दमदार सिनेमाई कहानी की संभावनाएं देखीं।इसके बाद फिल्म की कहानी को विकसित करने का सफर शुरू हुआ, जो लगभग पांच वर्षों तक चला। इस दौरान सुवेंदु भट्टाचार्य और विपुल अमृतलाल शाह ने मिलकर कहानी की संरचना, स्क्रीनप्ले के विभिन्न ड्राफ्ट और 1990 के आर्थिक संकट के राजनीतिक, वित्तीय और भावनात्मक पहलुओं पर गहन काम किया। फिल्म को सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना तक सीमित न रखकर, उस दौर के मानवीय संघर्ष और फैसलों की गंभीरता को भी कहानी में पिरोने की कोशिश की गई। जैसे-जैसे स्क्रिप्ट आगे बढ़ती गई, लेखक सौरभ भारत और रवि असरानी भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े। दोनों ने विपुल अमृतलाल शाह के साथ मिलकर स्क्रीनप्ले को और मजबूत बनाया तथा अंतिम संवादों को आकार दिया। सूत्रों के मुताबिक, लेखकों ने इस फिल्म की प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए वर्षों तक आर्काइव्स, पुराने समाचार पत्रों की रिपोर्ट्स, सरकारी दस्तावेजों और उस समय की वास्तविक घटनाओं का गहराई से अध्ययन किया।

सूर्या चौहान हत्याकांड के दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग, आईएचपी व राष्ट्रीय बजरंग दल ने सौंपा ज्ञापन

जौनपुर।
यूपी के जौनपुर में अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल की जौनपुर इकाई ने गाजियाबाद में सूर्या चौहान की हत्या के मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बुधवार को जिलाध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह के नेतृत्व में संगठन के कार्यकताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट इंद्र नंदन सिंह को सौंपा।

ज्ञापन में कहा गया कि बकरीद के दिन गाजियाबाद में सूर्या चौहान की निर्मम हत्या से समाज में गहरा दुख और आक्रोश व्याप्त है। इस घटना ने प्रदेशवासियों की भावनाओं को आहत किया है। संगठन ने मामले में एक आरोपित के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री एवं पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त किया। उनका कहना था कि इससे प्रदेश की जनता का कानून व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास मजबूत हुआ है।

जिलाध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह ने मांग की कि हत्या में शामिल शेष सभी आरोपितों तथा इस अपराध के षड्यंत्र में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाए।

उन्होंने कहा कि अपराधियों को ऐसा दंड मिलना चाहिए, जो समाज में एक मजबूत संदेश दे और भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की जघन्य घटना को अंजाम देने का साहस न कर सके।

इस अवसर पर कृष्ण कुमार उपाध्याय, यादवेन्द्र यादव, जितेंद्र बहादुर सिंह सहित संगठन के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

हीवेट चौराहा हत्याकांड: बहू और महिला मित्र की तलाश में पुलिस की ताबड़तोड़ दबिश

प्रयागराज।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित कोतवाली थाना क्षेत्र के हीवेट रोड चौराहे स्थित वैश्य परिवार के चार सदस्यों की हत्या के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) डॉ. अजय पाल शर्मा ने बताया कि मामले में मृतक वीरेंद्र कुमार वैश्य के छोटे बेटे अश्विनी वैश्य की कथित पत्नी रीतु वैश्य तथा बड़े बेटे अभिषेक वैश्य की महिला मित्र की तलाश की जा रही है। पुलिस की कई टीमें संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं।

डॉ. शर्मा ने बताया कि इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर विस्तृत जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि अश्विनी वैश्य वर्तमान में धोखाधड़ी के एक मामले में कौशाम्बी जेल में निरुद्ध है, जबकि उसके साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली रीतु वैश्य जमानत पर बाहर है।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि घटनास्थल से बरामद एक गत्ते पर हत्या के लिए "बहू और बंटी-बबली" को जिम्मेदार बताए जाने की बात सामने आई है, जिसे भी जांच के दायरे में रखा गया है। हालांकि पुलिस अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है और सभी पहलुओं की गहनता से पड़ताल कर रही है।

उन्होंने बताया कि घर से बरामद चौथे शव की पहचान को लेकर भी जांच जारी है। रिश्तेदार उसे अभिषेक वैश्य बता रहे हैं, लेकिन पोस्टमार्टम और अन्य औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही इसकी आधिकारिक पुष्टि की जा सकेगी।

संदिग्ध परिस्थितियों में महिला ने मायके में लगाई फांसी, मौत

फरुर्खाबाद।
जिले के जहानगंज थाना क्षेत्र में मायके में रह रही युवती शिल्पी का शव संदिग्ध परिस्थितियों फांसी के फंदे पर झूलता मिला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी।

ग्राम मुबारकपुर निवासी प्रशांत ने बुधवार को थाना पुलिस को अवगत कराया कि उसकी बहन (30) शिल्पी की शादी कोतवाली मोहम्मदाबाद के ग्राम शीशम नगला निवासी विजय सिंह के साथ वर्ष 2017 में हुई थी। पति से आपसी विवाद के कारण बहन शिल्पी, बेटी भूमि व बेटे कार्तिक को पढ़ाने के लिए फरुर्खाबाद रह रही थी। स्कूलों की छुट्टी होने के कारण बहन गांव मुबारिकपुर अपने मायके आई थी। दो जून की रात खाना खाकर अपने बच्चों के साथ बाहर छत पर लेटी थी। रात में शिल्पी ने किसी कारणवश फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब रात को बेटी की नींद खुली और मां को अपने पास नहीं देखा तो नानी तारावती को सूचना दी।

जब घर के लोगों ने शिल्पी की खोजबीन शुरू की तो कमरे के नीचे हाल में छत के कड़े में दुपट्टा से फांसी लटका हुआ था।

पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू की हेल्प लाइन, शिकायत दर्ज करने के लिए ईमेल

कोलकाता, 03 जून । पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को जनहित में हेल्प लाइन और ईमेल आईडी जारी किया है। इसके विभिन्न सरकारी सेवाओं को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए या राज्य सरकार से सीधे शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्प लाइन और ईमेल आईडी जारी किया गया है। हेल्प लाइन नंबर है 82820 8282 एवं ईमेल आईडी - पर भी शिकायत की जा सकती है। मिली जानकारी के अनुसार, यह सेवा सोमवार से शनिवार तक हर सप्ताह सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक चालू रहेगी।

पश्चिम बंगाल में 20 जून को मनाया जाएगा राज्य दिवस, कैबिनेट ने दी मंजूरी

कोलकाता, 03 जून । पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि 20 जून को आधिकारिक रूप से पश्चिम बंगाल राज्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने की। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पंचायत मंत्री दिलीप घोष ने

बताया कि 20 जून, 1947 को तत्कालीन बंगाल विधानसभा में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव ने बंगाल के विभाजन और पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया था। इसी ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 20 जून को पश्चिम बंगाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। दिलीप घोष ने कहा कि अब से हर वर्ष 20 जून को राज्य सरकार की ओर से आधिकारिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इससे पहले भाजपा 20 जून को पश्चिम बंगाल दिवस के रूप में मनाती रही है, जबकि पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार बंगाली नववर्ष पोइला बोइशाख के दिन, यानी 14 या 15 अप्रैल को राज्य दिवस मनाती थी। मंत्री ने यह भी घोषणा की कि जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पूरे राज्य में वर्षभर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाई जाएगी। डॉ. मुखर्जी की जयंती 6 जुलाई को मनाई जाती है।

उन्होंने बताया कि वर्षभर चलने वाले कार्यक्रमों के संचालन के लिए 10 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी, जिसमें मंत्री, विधायक और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा 6 जुलाई को एक विशेष समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें चयनित स्थान पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी।

मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की मां आहार योजना के विस्तार का भी निर्णय लिया गया। दिलीप घोष ने बताया कि वर्तमान में 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने वाली यह योजना राज्य के 390 केंद्रों पर संचालित हो रही है, जिसे बढ़ाकर 500 केंद्रों तक किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि, पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने मां कैंटीन परियोजना के तहत 5 रुपये में अंडा-चावल भोजन योजना शुरू की थी। भाजपा सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए समान दर पर मछली युक्त भोजन उपलब्ध कराना शुरू किया है। अब यह योजना मां आहार नाम से राज्य के 500 स्थानों पर संचालित होगी। राज्य सरकार का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य बंगाल के ऐतिहासिक महत्व को

सरकारी कर्मचारी समय पर नहीं पहुंचे तो अनुपस्थित माने जाएंगे

कोलकाता, 03 जून । पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति और समयपालन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। नवान्न की ओर से जारी नई अधिसूचना के अनुसार अब सभी सरकारी कर्मचारियों को निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचना और समय पूरा होने तक कार्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर अनुपस्थित दर्ज किया जाएगा और अवकाश भी काटा जा सकता है।सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, समयपालन सुनिश्चित करने, कार्यालयों में अनुशासन स्थापित करने और उपस्थिति रिकॉर्ड के डिजिटल संरक्षण के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की जा रही है। यह नई व्यवस्था नवान्न स्थित सभी विभागों में 15 जून से लागू होगी, जबकि 31 जुलाई तक चरणबद्ध तरीके से राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में इसे लागू कर दिया जाएगा। मंगलवार को राज्य की मंत्री अग्निमित्रा पाल ने भी कहा था कि प्रत्येक कर्मचारी को अपने काम के प्रति जवाबदेह होना होगा। उन्हें समय पर कार्यालय आना और समय पर ही कार्यालय छोड़ना होगा। सभी सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू की जाएगी। पश्चिम बंगाल सेवा नियमावली (भाग-1) के नियम 29ए के तहत कर्मचारियों को मुख्यालय से 8 किलोमीटर के भीतर निवास करने की अनिवार्यता से जो छूट पहले से प्राप्त है, वह जारी रहेगी।- नवान्न में कार्यरत सभी कर्मचारियों (विभागाध्यक्षों को छोड़कर) के लिए कार्यालय में प्रवेश और निकास का समय चेहरा पहचान पर आधारित बायोमेट्रिक प्रणाली से दर्ज करना अनिवार्य होगा। - सुबह 10:15 बजे से 11:00 बजे के बीच उपस्थिति दर्ज कराने पर कर्मचारी को विलंब से उपस्थित माना जाएगा। - सुबह 11:00 बजे के बाद उपस्थिति दर्ज कराने पर कर्मचारी को उस दिन अनुपस्थित माना जाएगा। - शाम 5:15 बजे से पहले कार्यालय छोड़ने पर इसे निर्धारित समय से पूर्व प्रस्थान माना जाएगा। - यदि कोई कर्मचारी एक ही दिन देर से पहुंचे और निर्धारित समय से पहले कार्यालय छोड़ दे, तो उसे उस दिन अनुपस्थित माना जाएगा तथा उसका एक दिन का आकस्मिक अवकाश काट लिया जाएगा।

- कार्यालय छोड़ते समय बायोमेट्रिक प्रणाली में आउट-पंच नहीं करने पर भी कर्मचारी को अनुपस्थित माना जाएगा। - किसी महीने में तीन बार देर से पहुंचने या समय से पहले कार्यालय छोड़ने पर एक दिन का आकस्मिक अवकाश अथवा बाल देखभाल अवकाश काटा जाएगा। - पश्चिम बंगाल सेवा नियमावली (भाग-1) के नियम 15 के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारियों को कार्यालय समय समाप्त होने के बाद भी सरकारी कार्य करना होगा। - यदि किसी कर्मचारी या अधिकारी को आधिकारिक बैठक अथवा सरकारी कार्य के कारण देर से आना या पहले जाना पड़े, तो संबंधित विभागाध्यक्ष आवश्यक अनुमोदन की व्यवस्था करेंगे। सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक अनुशासन स्थापित करने और सरकारी कार्यालयों में कार्य संस्कृति को अधिक जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

अधिकारियों का कहना है कि नई व्यवस्था से कर्मचारियों की उपस्थिति की निगरानी अधिक प्रभावी होगी और सरकारी सेवाओं के संचालन में पारदर्शिता बढ़ेगी।

ममता के धरने पर दिलीप घोष का कटाक्ष, कहा– उनके साथ कोई नहीं

कोलकाता, 3 जून : राज्य के पंचायत मंत्री दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी के धरने पर कटाक्ष किया है। बुधवार सुबह पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिलीप घोष ने कहा, यह कोई बहुत बड़ा आयोजन नहीं था। यह जबरदस्ती कराया गया कार्यक्रम था। पार्टी के सांसद और विविधायक भी इसमें शामिल नहीं हुए। केवल वही लोग वहां मौजूद थे, जिनके पास जाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं थी और जो विशेष लाभ पाने वाले हैं। उनके (ममता) साथ कोई नहीं है। दिलीप घोष ने आगे कहा, जो लोग कभी हमारे नेताओं के नाम लेकर गालियां दिया करते थे, वही अब उन्हें माला पहना रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। समय बदलता है, लेकिन उन्होंने क्या-क्या किया है, यह जनता जानती है। जनता जब इसका मूल्यांकन और फैसला करेगी, वह सही होगा। इसके विपरीत निर्णय लेने वाले हम कौन होते हैं? गुजरात के 70 प्रतिशत मकानों को अवैध बताए जाने संबंधी ममता बनर्जी के आरोप पर मंत्री दिलीप घोष ने कहा, क्या वह स्वयं जाकर जांच करके आई हैं कि वे मकान वैध हैं या अवैध? उनके अपने घर ही अवैध हैं–पहले इस बात को ध्यान में रखें। उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव के बाद तथा गठित हिंसा के खिलाफ मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस द्वारा कोलकाता में आयोजित धरना प्रदर्शन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल हुई थी। हालांकि बुलावे के बावजूद पार्टी के अधिकांश सांसद और विधायक इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए।

समय पर ड्यूटी नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई

कोलकाता , 02 जून । कोलकाता दौरे के दौरान मंगलवार को महिला और शिशु कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पाल ने सरकारी कार्यालयों और नगर निकायों के कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि जनता के टैक्स के पैसे से अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन मिलता है, इसलिए सभी को अपने कार्य के प्रति जवाबदेह होना होगा। उन्होंने कहा कि ग्रुप-सी और ग्रुप-डी कर्मचारियों सहित सभी कर्मियों को निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचना और पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। उन्होंने बताया कि सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू की जाएगी। साथ ही फील्ड में कार्य करने वाले निर्मल साथी और अन्य कर्मचारियों की भी बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज होगी। कर्मचारियों की गतिविधियों की निगरानी के लिए जियो-टैगिंग व्यवस्था भी लागू की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे निर्धारित कार्यस्थल पर कार्य कर रहे हैं या नहीं। अग्निमित्रा पाल ने कहा कि प्रत्येक कर्मचारी और अधिकारी को अपनी जवाबदेही समझनी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्य के प्रति लापरवाही अब स्वीकार नहीं की जाएगी।

भाजपा सरकार ने ह्यमां कैंटीनह्न का नाम बदलकर किया ह्यमां आहारह्न, योजना जारी रखने का किया ऐलान

कोलकाता, 03 जून । पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार ने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार की जनकल्याणकारी योजना ह्यमां कैंटीनह्न को जारी रखने का फैसला किया है। हालांकि, योजना का नाम बदलकर अब ह्यमां आहारह्न कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने राज्यभर में इस योजना के विस्तार की भी घोषणा की है। बुधवार को नवान्न में नई सरकार की पूर्ण मंत्रिपरिषद की पहली बैठक के बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री दिलीप घोष ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ह्यमां कैंटीनह्न योजना का नाम बदलकर ह्यमां आहारह्न रखा गया है और इसे पहले की तरह जारी रखा जाएगा।

दिलीप घोष ने कहा कि अभी तक राज्य में 390 केंद्रों से इस योजना के तहत भोजन उपलब्ध कराया जाता था। अब 110 नए ह्यमां आहारह्न केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके बाद राज्य में कुल 500 केंद्रों से लोगों को मात्र पांच रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि गरीब और जरूरतमंद लोगों को सस्ती दर पर पौष्टिक भोजन मिलता रहे। इसी उद्देश्य से योजना को बंद करने के बजाय उसका विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि, विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में सत्ता परिवर्तन होने पर कई लोगों ने आशंका जताई थी कि तृणमूल सरकार की इस लोकप्रिय योजना को बंद किया जा सकता है। हालांकि, भाजपा सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी जनकल्याणकारी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। सरकार ने यह भी संकेत दिया था कि भविष्य में योजना के भोजन मेन्यू में बदलाव कर अंडा-भात के स्थान पर मछली-भात शामिल करने पर विचार किया जा सकता है। गौरतलब है कि ह्यमां कैंटीनह्न योजना की शुरूआत 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर की गई थी। सबसे पहले दक्षिण कोलकाता के देशप्रिय पार्क क्षेत्र में श्रमिकों के लिए 5 रुपये में दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया गया था। योजना के तहत लोगों को 5 रुपये में चावल, दाल और अंडे की सब्जी अथवा उबला अंडा दिया जाता था। मुख्य रूप से सरकारी अस्पतालों के बाहर आने वाले गरीब मरीजों और उनके परिजनों को कम लागत में भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना की शुरूआत की गई थी।

नई सरकार के फैसले के बाद अब ह्यमां आहारह्न के नाम से यह योजना राज्यभर में और अधिक केंद्रों के माध्यम से संचालित की जाएगी।

दक्षिण 24 परगना के कुलतली में हिरासत में लिये गये 18 बांग्लादेशी

कोलकाता, 3 जून (हि.स.) : दक्षिण 24 परगना जिले के कुलतली थाना क्षेत्र के गोदाबर इलाके से कुलतली थाना पुलिस ने 18 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। इस समूह में 12 वयस्क पुरुष एवं महिलाएं तथा छह बच्चे शामिल हैं। इनमें से किसी के पास भी वैध दस्तावेज नहीं मिले हैं। गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए एक विशेष अभियान में बुधवार तड़के कुलतली के गोदाबर क्षेत्र स्थित एक स्थानीय ईंट-भट्टे से कुल 18 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया। पुलिस के अनुसार, हिरासत में लिए गए लोगों में 12 वयस्क पुरुष एवं महिलाएं हैं, जबकि शेष 6 बच्चे हैं। बिना किसी वैध दस्तावेज के अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर वे पिछले कई वर्षों से भारत में रह रहे थे। पूछताछ के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों ने स्वीकार किया कि वे सभी एक प्रभावशाली दलाल गिरोह की मदद से अवैध रूप से कंटीले तारों की बाड़ पार कर भारत में प्रवेश किए थे। बांग्लादेश सीमा पार कराने के लिए उन्हें सीमा क्षेत्र में सक्रिय अंतरराष्ट्रीय दलालों को प्रति व्यक्ति 5 हजार रुपये से लेकर अधिकतम 30 हजार रुपये तक भुगतान करना पड़ा था।

पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों को होल्डिंग सेंटर में भेजने की तैयारी कर रही है।

तृणमूल नेता जयप्रकाश मजूमदार गिरफ्तार, फ्लैट पर अवैध कब्जे और मकान मालकिन को धमकाने

कोलकाता, 03 जून। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश मजूमदार को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। उन पर एक फ्लैट पर वर्षों से अवैध कब्जा करने, उसकी वृद्ध मकान मालकिन को कथित रूप से धमकाने और अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगे हैं। पुलिस ने उन्हें विधाननगर उत्तर थाना क्षेत्र से हिरासत में लेने के बाद औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार, जयप्रकाश मजूमदार ने वर्ष 2012 में विधाननगर के एई-337 नंबर फ्लैट को किराये पर लिया था। आरोप है कि वर्ष 2015

में एग्रीमेंट की अवधि समाप्त होने के बावजूद उन्होंने एग्रीमेंट का नवीनीकरण नहीं कराया। इसके बावजूद वह और उनका परिवार फ्लैट में रह रहे थे। फ्लैट की मालिक आरती रायचौधुरी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने कई बार कानूनी नोटिस भेजकर फ्लैट खाली करने को कहा था, लेकिन जयप्रकाश मजूमदार और उनके परिवार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आरती ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें अपमानजनक टिप्पणियां की गईं और धमकियां दी गईं।

बुधवार को इस मुद्दे को लेकर कुछ लोग फ्लैट के बाहर एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान जयप्रकाश मजूमदार ने कुछ प्रदर्शनकारियों के साथ धक्का-मुक्की और हाथापाई की।

बंगाल बजट से पहले उद्योग जगत से सरकार की चर्चा, निवेश और कारोबार सुगमता पर जोर

कोलकाता, 02 जून । पश्चिम बंगाल सरकार के वित्त विभाग ने मंगलवार को आगामी राज्य बजट से पहले उद्योग मंडलों और व्यापारिक संगठनों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की। राज्य में भाजपा सरकार के पहले बजट से पूर्व आयोजित इस बैठक में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने निवेश बढ़ाने, कारोबार को आसान बनाने और आधारभूत ढांचे के विकास के लिए विभिन्न सुझाव दिए।

वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रभात कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स, क्रेडाई, एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ समेत कई उद्योग एवं व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में राज्य कर आयुक्त खालिद अनवर सहित राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार, सरकार ने बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देने से पहले उद्योग और व्यापार जगत की राय जानने के उद्देश्य से यह बैठक आयोजित की। बैठक में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रतिनिधियों ने आगामी बजट को लेकर अपनी अपेक्षाएं और सुझाव रखे। चर्चा के दौरान निवेश प्रोत्साहन, हल्दिया औद्योगिक क्षेत्र का विकास, सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा, व्यापार लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाने, एकल खिड़की स्वीकृति व्यवस्था को मजबूत करने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा रियल एस्टेट और निर्माण क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए। भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स ने राज्य में कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए अपनी सिफारिशों वाला एक ज्ञापन सरकार को सौंपा और आवश्यक नीतिगत उपायों पर प्रस्तुति भी दी। राज्य का बजट 22 जून को विधानसभा में पेश किया जाना प्रस्तावित है, जबकि बजट सत्र 18 जून से शुरू होगा। हालांकि भाजपा सरकार अभी तक राज्य के वित्त मंत्री के नाम की घोषणा नहीं कर पाई है। पार्टी विधायकों के अनुसार, सोमवार को 35 मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद विस्तारित मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा बुधवार को किया जा सकता है। उद्योग जगत की नजर सरकार की भूमि और औद्योगिक नीति पर भी टिकी हुई है। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शमिक भट्टाचार्य ने भूमि सीमा कानून की समीक्षा की वकालत करते हुए कहा था कि बड़े औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए भूमि की उपलब्धता आसान बनाना आवश्यक है।

अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत रिषड़ा में 100 लाभार्थियों को मिला योग्यता प्रमाण पत्र

हुगली, 03 जून । मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा भंडार योजना की औपचारिक शुरूआत कर दी। इस योजना के तहत राज्य की योग्य महिलाओं को प्रतिमाह तीन हजार रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से भेजी जाएगी। योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना तथा घरेलू खर्चों एवं स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग प्रदान करना है। इसी क्रम में रिषड़ा के रवींद्र भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में अन्नपूर्णा भंडार योजना के 100 लाभार्थियों को योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि सभी योग्य लाभार्थियों के बैंक खातों में शीघ्र ही योजना के तहत निर्धारित सहायता राशि भेजी जाएगी। इस अवसर पर रिषड़ा नगरपालिका के चेयरमैन विजय सागर मिश्रा, वाइस चेयरमैन जाहिद हसन खान, पार्षद शशि सिंह झा, पार्षद मनोज सिंह, पार्षद सुख सागर मिश्रा, नगरपालिका के एक्जीक्यूटिव ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर सहित अन्य अधिकारी एवं पार्षदगण उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है। अन्नपूर्णा भंडार योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे महिलाओं को नियमित वित्तीय सहायता प्राप्त होगी और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा।

सरकारी जमीन पर कब्जे के आरोप में प्रदर्शन

हुगली, 03 जून । श्रीरामपुर के तारापुकुर इलाके में सरकारी जलाशय (वेटलैंड) को भरकर अवैध निर्माण किए जाने के आरोप में स्थानीय निवासियों ने बुधवार को विरोध-प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जलाशय को भरकर जमीन की बिक्री किए जाने से इलाके की जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है और थोड़ी सी बारिश में भी जलभराव की समस्या उत्पन्न हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने 27 नंबर वार्ड के पार्षद पिंटू नाग पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और निर्माण को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने अवैध निर्माण को हटाने तथा सरकारी जमीन को पुनः मुक्त कराने की मांग की। र्ता पायल राय ने कहा कि जलभराव की समस्या के कारण डेंगू सहित विभिन्न बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगरपालिका की ओर से इस समस्या के समाधान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। हालांकि, पार्षद पिंटू नाग ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने फोन पर कहा कि जिस जमीन को लेकर उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, वह जमीन उनके वार्ड के अंतर्गत ही नहीं आती। उनके अनुसार संबंधित जमीन सरकारी नहीं है और उसकी खरीद-बिक्री कई वर्ष पहले ही हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस मामले से उनका कोई संबंध नहीं है और उन्हें बेवजह विवाद में घसीटा जा रहा है।

सरकारी कार्यालयों में नकबजनी की वारदातें करने वाले मुख्य सरगना निर्मल को किया गिरफ्तार

श्री हनुमान प्रसाद, आईपीएस, पुलिस अधीक्षक, जिला जयपुर ग्रामीण ने जानकारी देते हुये बताया है कि दिनांक 08.04.26 को श्री देवीलाल पुत्र नाथुराम जाति जाट निवासी रामजीपुरा खुर्द पुलिस थाना रेनवाल जिला जयपुर ने रिपोर्ट दर्ज करवायी की दिनांक 08.04.2026 को पंचायत चपरासी श्री गोपाल लाल कुम्हार पंचायत का गेट खोलने आया तो चैनल गेट, ई-मित्र कियोस्क व सरपंच श्ऊद्व कार्यालय व सामने हाल के ताले टूटे हुए मिले। चपरासी गोपाल लाल कुम्हार ने ई-मित्र कियोस्क संचालक मुकेश कुमार यादव को फोन कर बुलाया व आसपास के सभी गांव वाले भी इकट्ठा हो गये। पुलिस थाना रेनवाल पर सूचना देने पर रेनवाल पुलिस द्वारा ग्राम पंचायत में आकर मौका मुआयना किया गया व सामान की जाच की गई तो ई-मित्र कियोस्क से मुख्य तौर पर लेपटाप, मंतरा डिवाईस, यूपीएस व कार्यालय सरपंच सचीव से एलसीडी मोनीटर नही मिला। उक्त सामान के अलावा रिकॉर्ड से भी छेड़छाड़ करना पाया गया व कार्यालय की अलमारी का ताला टूटा हुआ मिला। आदि रिपोर्ट पर अभियोग संख्या 95/26 धारा 331(4), 305 (ए) इठर में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस द्वारा दिनांक 29.05.2026 को पुलिस थाना रेनवाल पर दर्ज नकबजनी के प्रकरण संख्या 106/26, 138/26 व 145/26 में खुलासा करते हुए नकबजनी करने वाले 04 आरोपियों जितेन्द्र, रोहित, रमेश, अशोक कुमार एंव चोरी का माल खरीदने वाले आरोपी मोहम्मद रफीक, अशरफ कुरेसी को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों से पूछताछ की गई तो आरोपियों ने रेनवाल, कालाडेरा, सांभरलेक, गोविन्दगढ, दांतारामगढ, खाटुश्यामजी सदर।

खाटुश्यामजी कोतवाली, खोरा बिसल व फुलेरा में नकबजनी की 17 वारदातें करना बताया था। उक्त सभी वारदातों में मुख्य आरोपी निर्मल पुत्र श्रीराम जाति यादव निवासी नाथी का बास पुलिस थाना रेनवाल जिला जयपुर ग्रामीण फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री रजनीश पूनियाँ व वृत्ताधिकारी जोबनेर श्री शिवरतन गोदारा के निकटतम सुपरवीजन में तथा थानाधिकारी रेनवाल श्रीमती नरेश कंवर पुलिस निरीक्षक, श्री सतेन्द्र सउनि डीएसटी मय जाप्ता के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीम में से श्री सतेन्द्र सउनि डीएसटी टीम मय जाप्ता द्वारा आसूचना।

संकलन व तकनीकी सहायता द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए नकबजनी के मुख्य आरोपी निर्मल को कस्बा गोविन्दगढ से डिटेन किया गया तथा प्रकरण का माल मसरूका 01 यूपीएस व 01 मंतरा डिवाईस कस्बा रींगस में कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर की दुकान से बरामद कर पुलिस थाना रेनवाल को सुपुर्द किया गया।

गुल्लक से पैसे चुराने वाले शातीर नकबजन अक्षय सोनी उर्फ बिट्टू शूटर को किया गिरफ्तार

श्री हनुमान प्रसाद,आईपीएस, पुलिस अधीक्षक, जिला जयपुर ग्रामीण ने जानकारी देते हुए बताया है कि दिनांक 23/04/2026 को परिवादी राकेश पुत्र शंकरलाल जाति कुम्हार निवासी छोटा बाजार सांभरलेक थाना सांभरलेक जिला जयपुर ने रिपोर्ट दर्ज करवायी की मैं कस्बा फुलेरा में डॉक्टर श्री महेश कंडेल प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (स्त्री रोग) उप जिला अस्पताल फुलेरा जिला जयपुर के पास क्लीनिक पर काम करता हूँ। दिनांक 23.04.2026 को मेरे पास डॉक्टर साबह के क्नीनिक पर काम करने वाली महिला मंजू देवी ने मेरे को फोन करके बताया कि मरीज परीक्षक कक्ष में गौशाला के लिए रखे हुए गुल्लक का ताला टूटा हुआ है और उसमें रखे हुए पैसं कोई चुरा कर ले गया है जिस पर मैने जाकर देखा तो गुल्लक का ताला टूटा हुआ व उसमें रखे हुए पैसे नही मिले। आदि रिपोर्ट पर पुलिस थाना फुलेरा पर मुकदमा नम्बर 94/2026 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। प्रकरण में अज्ञात आरोपी को गिरफ्तार करने हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दूदू श्री शिवलाल बैरवा व वृत्ताधिकारी सांभरलेक श्री अनुपम मिश्रा के निकटतम सुपरविजन में तथा थानाधिकारी फुलेरा श्री राजेन्द्र कुमार पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा आसूचना संकलन व तकनीकी सहायता द्वारा अथक प्रयास करते हुए प्रकरण के संदिग्ध आरोपी अक्षय सोनी उर्फ बिट्टू शूटर को कस्बा फुलेरा से डिटेन कर पूछताछ की तो चोरी की वारदात करना स्वीकार किया। आरोपी से पूछताछ की तो नशे की लत पूरी करने हेतु चोरी करना बताया।

दिनांक 01.06.2026 को आरोपी को प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है तथा आरोपी से माल बरामदगी के प्रयास जारी है।

जयपुर यातायात पुलिस द्वारा मॉडिफाईड वाहन चलाने वाले को कडा संदेश

जयपुर पुलिस आयुक्त श्री सचिन मित्तल ने मोटर यान अधिनियम 1988 यथा संशोधित मोटर यान (संशोधन) अधिनियम 2019 में वर्णित प्रावधानों के तहत एवं सडक दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु वाहन में अनाधिकृत मॉडिफिकेशन, ब्लैक फिल्म, शराब पीकर वाहन चलाना, निर्धारित गति से तेज गति में वाहन चलाने वाले वाहन चालक / स्वामियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। पुलिस उपायुक्त यातायात श्री योगेश गोयल ने बताया कि आयुक्तालय जयपुर में टीम गठित कर नियमित विशेष अभियान चलाया जाकर उल्लंघनकर्ता चालक / स्वामियों के विरूद्ध नियमित कार्यवाही की जा रही है। यातायात पुलिस द्वारा चलाये जा रहे उक्त अभियान में दिनांक 03.06.2026 को सहायक पुलिस आयुक्त श्री प्रेम सिंह के नेतृत्व में किसान धर्मकांटा पर सहायक उपनिरीक्षक श्री गोपाल सिंह द्वारा अवैध मोडिफिकेशन, काली फिल्म वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की गई है, गठित टीम द्वारा कुल 15 वाहनों को एम.वी. एक्ट में नियमानुसार जप्त किया गया है, जब्त वाहनों में 04 थार व 11 स्कापियो वाहन है, वाहनों पर ब्लेक फिल्म लगी पाई गई एव वाहन को नियम विरूद्ध मोडीफाइड किया गया था। उक्त जब्त वाहनों के अलावा यातायात पुलिस द्वारा एम.वी. एक्ट की कार्यवाही में कुल 36 अन्य वाहनों को भी जप्त किया गया है। यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग के संयुक्त अभियान के तहत टोल प्लाजा पर अवैध मोडिफिकेशन, काली फिल्म वाले 65 वाहनों पर कार्यवाही की गई है। श्री गोयल ने बताया कि सडक दुर्घटना की दृष्टि से एसयूवी वाहनों पर मोडीफाईड बंपर होने से एयरबैग खुलने में समस्या आने की संभावना रहती है जिससे दुर्घटना के दौरान जोखिम बढ जाता है। अतः वाहनों पर मॉडिफाईड बंपर नहीं लगाने की अपील की है।

विधायक रामसहाय वर्मा का औचक निरीक्षण ,बिजली दफ्तर और रेलवे स्टेशन पर खुली लापरवाही की पोल

टोंक। निवाई भीषण गर्मी में चरमराई व्यवस्थाओं को लेकर विधायक रामसहाय वर्मा ने बिजली दफ्तर और रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। इस औचक कार्रवाई से लापरवाह अधिकारियों में हड़कंप मच गया।बिजली दफ्तर में कई कर्मचारी गायब मिले। पिछले कही दिनों से रोजाना हो रही अघोषित बिजली कटौती, स्टोर से सामान न मिलने और सहायक अभियंता द्वारा फोन न उठाने पर विधायक ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई।इसके बाद रेलवे स्टेशन पहुंचे विधायक को रिजर्वेशन काउंटर बंद मिला। हद तो तब हो गई जब प्लेटफॉर्म के वाटर कूलर की टंकी में कचरा और पानी बेहद गर्म मिला। विधायक ने स्टेशन मास्टर को जमकर लताड़ लगाई और उच्चाधिकारियों को फोन कर तुरंत व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान भाजपा शहर अध्यक्ष नितिन छाबड़ा, मंडल अध्यक्ष केदार दोहण, , एडवोकेट देवराज गुर्जर समेत अन्य भाजपा नेता उपस्थित थे

कृषि भूमि पर जबरन कब्जा कर फर्जी पट्टे तरीक आरोपी कमलेश कुमार को किया गिरफ्तार

श्री हनुमान प्रसाद (आईपीएस), जिला पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण ने जानकारी देते हुए बताया है कि दिनांक 10.10.25 को परिवादी कजोड लाल बैरवा ने रिपोर्ट पेश की कि मेरी पत्नी के स्वामित्व व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 629 रकबा 0.7461 हैक्टेयर ग्राम डाबला बुजुर्ग पटवार हल्का मोहब्बतपुरा, भू. अभि. निरीक्षक क्षे. रेनवाल मांजी तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर में स्थित है, दिनांक 09.10.2025 को अपनी कृषि भूमि पर गया तो कुछ लोग भूमि में से मिट्टी उठा रहे थे। उनमें रामवतार सैन, लोकेन्द्र राजपुत, अजयसिंह, विकास चौधरी, जयसिंह मीणा, बनवारी यादव तथा खुदाबादी सोनार कॉपरेटिव हाउसिंग सोसायटी जयपुर का व्यक्ति / पदाधिकारी कमलेश कुमावत, निवासीः-बाजडोली, वाटिका, जयपुर एवं उसके साथ आये राजेश गुर्जर ने मुझे कहा कि तुम अपनी जमीन हमे बेच दो। मैंने उनको बेचने से मना करने पर उन्होने मुझे धमकाया और जमीन पर कब्जा करने व दबाव बनाकर मुझे मेरी कृषि से बेदखल करने का प्रयास कर जातिसूचक शब्दो से अपमानित किया है। मेरी पत्नी मोहर बाई ने उपरोक्त जमीन पूर्व में ओमप्रकाश पुत्र शंकरलाल जाति बैरवा, निवासीः करेडा गुर्जर, तहसील निवाई, जिला टोंक को इकरारनामा पर दिनांक 28.11. 2024 को विक्रय की थी परन्तु ओमप्रकाश द्वारा विक्रय मूल्य की राशि अदा नही करने पर मेरी पत्नी द्वारा दिनांक 02.05.2025 को विधिक नोटिस प्रेषित करवाया तत्पश्चात केता ओमप्रकाश ने मुझसे व मेरी पत्नी मोहर बाई से सम्पर्क कर विक्रयशुदा भूमि का विक्रय मूल्य की राशि अदा करने में असमर्थता व्यक्त कर मेरी पत्नी को सायपेटे दी गयी राशि क्रेता ओमप्रकाश ने वापस लौटाने की मांग कर बिचौति इकरारनामा दिनांकित 29.11.2024 निरस्त करने की सहमति जतायी जाने पर मैंने व मेरी पत्नी मोहर बाई ने विकय मूल्य के सायपेटे केता ओमप्रकाश से प्राप्त सम्पूर्ण राशि जरिये नगद व बैंक के माध्यम से अदा कर दी।

केता ओमप्रकाश ने एक निरस्तीकरण पत्र दिनांक 18.09.2025 को निष्पादित कर बिचौति इकरारनामा दिनांकित 29.11.2024 को निरस्त कर लिया, इस प्रकार मेरी पत्नी की उपरोक्त कृषि भूमि में किसी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं रहा, परन्तु उपरोक्त व्यक्ति ताकत के बल पर फर्जी पट्टे बनाकर मैं और मेरी पत्नी दलित वर्ग के होने के कारण डरा धमकाकर जबरन भूमि क्रय करने व कब्जा करने का प्रयास उपरोक्त लोगो द्वारा किया जा रहा है, आदि पर प्रकरण संख्या 139/2025 धारा 115 (2),126 (2),352,351 (2),329 (3) BNS 2023 व 3-(1)(R)(S), 3-2(श्अ) SC/ST ACT दिनांक 10.10.2025 पुलिस थाना रेनवाल मांजी जिला जयपुर ग्रामीण में दर्ज कर अनुसंधान क्रमशः श्री रामधन सांडीवाल आरपीएस तत्कालिन वृत्ताधिकारी वृत्त फागी व श्री अनिल कुमार डोरिया आरपीएस, वृत्ताधिकारी, वृत्त फागी श्री नीरज गुप्ता आरपीएस प्रो. वृत्ताधिकारी वृत्त फागी जिला जयपुर द्वारा किया गया। प्रकरण में मुल्जिम की गिरफ्तारी हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दूदू श्री शिवलाल बैरवा आरपीएस के निकटतम सुपरविजन में श्री नीरज गुप्ता आरपीएस प्रो. वृत्ताधिकारी फागी के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर आसूचना संकलन कर प्रकरण में फरार अपराधी कमलेश कुमार को दिनांक 02.06.2026 को गोमती नगर सांगानेर कोर्ट के पास, पुलिस थाना मालपुरा गेट सांगानेर से डिटेन कर कर प्रकरण में अनुसंधान किया गया। आरोपी द्वारा परिवादी की जमीन हडपने की नियत से धोखाधडी कर खुदाबादी सोना को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि. जयपुर के संयोजक का कार्य करते हुये आरोपी कमलेश कुमार द्वारा रामावतार सैन और अन्य व्यक्ति के नाम से फर्जी आवंटन पत्र जारी किये गये।

पतंजलि निशुल्क योग भजन पाठशाला सहयोग से पर्यावरण दिवस के उपलक्ष में वृक्षरोपण

आगरा, पालीवाल पार्क, आगरा में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम योग प्रशिक्षक त्रिलोकी नाथ बांसल जी एवं पवन वर्मा जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिसमें पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए 450 पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर महक सिंघल ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि वृक्ष मानव जीवन का आधार हैं। पेड़-पौधे हमें शुद्ध वायु, छाया, फल-फूल तथा प्राकृतिक संतुलन प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए वृक्षारोपण अत्यंत आवश्यक है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिवर्ष कम से कम एक पौधा लगाकर उसका संरक्षण करने का संकल्प ले, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ एवं हरित वातावरण सुनिश्चित किया जा सकता है। कार्यक्रम में सभी सदस्यों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हुए उत्साहपूर्वक पौधारोपण किया तथा लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल करने का भी प्रण लिया। महक सिंघल ने सभी नागरिकों से अधिक से अधिक वृक्ष लगाने और उन्हें संरक्षित करने का आह्वान किया। इस अवसर पर सत्यपाल बद्र जी, महक सिंघल, सारिका अग्रवाल, जया गोयल, आशी अग्रवाल, विजय अग्रवाल, राजकुमार बंसल, मीनू बंसल, गोविंद, हरि किशन वर्मा,मीनाक्षी, आवि सिंह एवं सुरेंद्र कौर सहित अनेक पर्यावरण प्रेमी उपस्थित रहे।

भ्रांतियों से बचें, बेटियों का भविष्य सुरक्षित करें: 14 वर्ष की सभी बालिकाओं को अवश्य लगवाएं एचपीवी (HPV) वैक्सीन

मेड़ता सिटी(लक्ष्मीनारायण वैष्णव) /चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, मेड़ता खंड द्वारा एचपीवी वैक्सीन अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जन-जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज एक विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया।

प्रेस वार्ता में प्रशासनिक अधिकारियों एवं चिकित्सा विशेषज्ञों ने भाग लेकर वैक्सीन से संबंधित भ्रांतियों का वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर खंडन किया तथा अभिभावकों से अपनी बेटियों का समय पर टीकाकरण करवाने की अपील की। एचपीवी वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित एवं प्रभावी है झ्र डॉ. महेन्द्र बिश्नोई, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेड़ता ने प्रेस वार्ता कर कहा कि एचपीवी वैक्सीन बालिकाओं को भविष्य में होने वाले गर्भाशय ग्रीवा (सर्वाइकल) कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा, "कुछ स्थानों पर यह भ्रांति फैलाई जा रही है कि एचपीवी वैक्सीन से भविष्य में संतानोत्पत्ति संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जबकि यह दावा पूरी तरह निराधार एवं वैज्ञानिक तथ्यों के विपरीत है। यह वैक्सीन सुरक्षित, प्रभावी तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा मान्यता प्राप्त है। हमारा लक्ष्य मेड़ता खंड की प्रत्येक पात्र बालिका तक इस सुरक्षा कवच को पहुंचाना है।" डॉ. बिश्नोई ने सभी अभिभावकों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और अपनी बेटियों का समय पर टीकाकरण अवश्य करवाएं। समय पर टीकाकरण से मिलेगी आजीवन सुरक्षा झ्र डॉ. बलदेव राम सियाग वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. बलदेव राम सियाग ने बताया कि 14 वर्ष तक की आयु में एचपीवी वैक्सीन लगवाना सर्वाधिक लाभकारी होता है। इस आयु में शरीर में बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है, जिससे भविष्य में सर्वाइकल कैंसर सहित एचपीवी संक्रमण से जुड़ी गंभीर बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। उन्होंने कहा कि यह टीका पूरी तरह सुरक्षित एवं वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है तथा अभिभावकों को किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं आना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने ली ऊर्जा विभाग की उच्चस्तरीय बैठक

जयपुर, 03 जून। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश को वर्ष 2027 तक बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना हमारा लक्ष्य है। इसके लिए ऊर्जा विभाग विद्युत उत्पादन और प्रसारण के क्षेत्र में कुशल प्रबंधन से कार्य करे। उन्होंने कहा कि थर्मल, हाइड्रो, सोलर, विंड जैसे माध्यमों से किसानों, उद्योगों और आमजन को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर ऊर्जा विभाग की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान की पहचान बिजली खरीदने वाला नहीं, बल्कि बिजली बेचने वाला अग्रणी प्रदेश के रूप में ओर अधिक मजबूत हो, इसके लिए विभागीय अधिकारी पूर्ण जिम्मेदारी से कार्ययोजना के अनुसार काम करें। उन्होंने कहा कि विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण से जुड़े कार्यों को गति प्रदान की जाए। साथ ही, 26 जिलों में किसानों को दिन में मिल रही बिजली की सुविधा को शेष जिलों में लागू करने के प्रयासों में भी तेजी लाई जाए। उन्होंने अधिक से अधिक संख्या में हितधारकों को पीएम कुसुम योजना और पीएम सूर्य घर योजना से लाभांवित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी डिस्कॉम विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए समन्वय से कार्य करें। साथ ही, उन्होंने जोधपुर डिस्कॉम में आरडीएसएस के शेष कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के लिए शिकायत निवारण तंत्र को तकनीकी स्तर पर ओर अधिक प्रभावी बनाया जाए।

बैठक में बताया गया कि उत्पादन निगम की कोयला आधारित विद्युत इकाइयों ने 02 जून को सर्वाधिक क्षमता का उपयोग कर 7 हजार 171 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया। इसी प्रकार गत वर्ष मई माह में कुल बिजली आवश्यकता की 8 प्रतिशत बिजली खरीदी गई। वहीं, ठोस एवं प्रभावी प्रयासों से समान अवधि में इस वर्ष महज 2 प्रतिशत बिजली की ही खरीद की गई है। उन्होंने कहा कि विद्युत उत्पादन इकाइयों की क्षमता में वृद्धि के लिए भी जरूरी कदम उठाए जाएं।

इसी तरह बताया गया कि राज्य सरकार के ढाई वर्ष के कार्यकाल में 400 केवी, 220 केवी और 132 केवी के 60 जीएसएस स्थापित हो चुके हैं। वहीं, 151 जीएसएस का कार्य प्रगति पर है। साथ ही, इसी समयावधि में 33 केवी के 444 सब स्टेशन स्थापित हुए हैं तथा 211 सब स्टेशन का कार्य प्रगति पर है।

बैठक में ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) अखिल अरोड़ा, ऊर्जा विभाग शासन सचिव आरती डोगरा सहित ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

थाना आदर्श नगर में घाटगेट बस स्टेण्ड पर अवैध रूप से सट्टा खेलते हुए 08 सटोरिये गिरफ्तार

पुलिस आयुक्त, जयपुर श्री सचिन मित्तल के मार्गदर्शन में विशेष पुलिस आयुक्त (ऑपरेशन्स), जयपुर श्री ओम प्रकाश के निर्देशन में श्री संजीव नैन, पुलिस उपायुक्त, अपराध के निकट सुपरविजन एवं नेतृत्व में C.S.T. आयुक्तालय जयपुर की टीम द्वारा जयपुर शहर में अवैध गतिविधियों एवं अपराधियों के खिलाफ आसूचना संकलित कर पुलिस थाना आदर्श नगर जयपुर (पूर्व) में आरोपीगण द्वारा अवैध रूप से सट्टा खेले हुए पाये गये। जिनके खिलाफ कार्यवाही कर 08 आरोपियों को गिरफ?तार किया गया।

थाना आदर्श नगर

जयपुर शहर में आदर्श नगर ईलाके में खडे वाहनों एवं थडी ठलों की आड़ से होते हुए घाटगेट बस स्टेण्डद पर स्थित थडियों के पीछे व दिवार के मध्य खाली जगह में कुछ लोग सट्टा खेल रहे है, की सूचना पर सट्टे के खिलाफ कार्यवाही की जाकर अवैध रूप से संगठित गिरोह बनाकर सट्टेबाजी का काम करने वाले 08 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी मुदस्सिर पुत्र श्री आसिफ अली द्वारा घाटगेट बस स्टेण्ड पर आम लोगों को सट्टा खिलाता है। जिसके संबंध में पुलिस थाना आदर्श नगर जयपुर (पूर्व) में प्रकरण संख्या 133/2026 धारा 13 आरपीजीओ एक्ट में दर्ज किया गया। आरोपीगणों से पूछताछ जारी है।

सोजत: श्री वैधनाथ महादेव मंदिर में हुआ भव्य रुद्राभिषेक, जन्मदिवस पर समाजसेवी जोगेश जोशी का हुआ नागरिक अभिनंदन।

अकरम खान, सोजत। प्राचीन एवं ऐतिहासिक श्री वैधनाथ महादेव मंदिर में आयोजित रुद्राभिषेक कार्यक्रम में श्रद्धालुओं एवं गणमान्य नागरिकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। कार्यक्रम के यजमान पूर्व पार्षद जोगेश जोशी (लक्की जोशी) रहे, जिन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान महादेव का विधिवत अभिषेक एवं पूजा-अर्चना की। रुद्राभिषेक का आयोजन विद्वान पंडित सत्यनारायण अवस्थी एवं हरगोविंद अवस्थी के सान्निध्य में संपन्न हुआ। मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से सराबोर रहा तथा श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आराधना कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा गणमान्य नागरिकों ने पूर्व पार्षद और समाजसेवी जोगेश जोशी का साफा एवं माल्यार्पण कर स्वागत किया तथा उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं प्रेषित कीं। उपस्थित जनों ने उनके सामाजिक योगदान एवं जनसेवा की सराहना करते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान राजेश सिंह कच्छवाह,भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश पंवार,पाली जिला भाजपा उपाध्यक्ष नरपतराज सोलंकी, भाजपा नेता जुगल किशोर निकुंम, सहायक लोक अभियोजक पंकज त्रिवेदी, वरिष्ठ नागरिक समिति के हितेंद्र व्यास, अभिनव कला मंच के सचिव चेतन व्यास, प्रफुल्ल ओझा, अखिल भारतीय गुरु फूलनारायण आश्रम न्यास के अध्यक्ष सुरेंद्र त्रिवेदी, बुढ़ायत माता मंदिर व्यवस्था समिति के अध्यक्ष जितेंद्र व्यास,पूर्व पार्षद तरुण सोलंकी,भरत जोशी, रमेश व्यास, अशोक शर्मा, जितेंद्र श्रीमाली, अशोक बारहठ, संतोष सिंह, उम्मेद सिंह सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र मुद्दों को लेकर आज जमकर हंगामा हुआ

प्रदर्शन के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हुई। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए बल प्रयोग किया और छात्रों को खदेड़ा। इस दौरान तीन छात्रों को हिरासत में भी लिया गया। घटना के बाद परिसर में कुछ समय तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा। राष्ट्रीय संयोजक, राज्य विश्वविद्यालय, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारत भूषण यादव ने कहा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में लगातार फीस बढ़ाई जा रही है, जबकि छात्रों को बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कैंपस में पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और कई भवनों की हालत जर्जर हो चुकी है। जिन जगहों पर छात्र बैठते हैं, वहां छतों से प्लास्टर गिरने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्रों से मोटी फीस वसूल रहा है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर स्थिति बेहद खराब है। इसके साथ ही लंबे समय से छात्रसंघ चुनाव भी नहीं कराए जा रहे हैं, जिससे छात्रों का लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हो रहा है। भारत भूषण यादव ने कहा कि परिषद के कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण और गांधीवादी तरीके से कुलपति सचिवालय पहुंचे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने छात्रों के साथ सख्ती बरती। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों की आवाज दबाने के लिए पुलिस कार्रवाई की गई, जिसे परिषद किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों की पांच सूत्री मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करेगी।

पीएम श्री विद्यालय सोजत सिटी में (CGIF) द्वारा अत्याधुनिक 'निहाल ऑडिटोरियम' का निर्माण कार्य शुरू

देश का दर्पण न्यूज सोजत संवाददाता अकरम खान, सोजत। चारण गढ़वी इंटरनेशनल फाउंडेशन (CGIF) के तत्वावधान में पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सोजत सिटी में अत्याधुनिक निहाल ऑडिटोरियम के निर्माण कार्य का शुभारंभ हो गया है। यह कार्य वरिष्ठ नागरिक समिति के अध्यक्ष सुरेश ओझा एवं विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की प्रेरणा तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य स्वरूपसिंह उदावत के आग्रह पर चारण गढ़वी इंटरनेशनल फाउंडेशन (CGIF) द्वारा इसका निर्माण करवाया जा रहा है।

चारण गढ़वी इंटरनेशनल फाउंडेशन के ग्लोबल अध्यक्ष एवं समाजसेवी अनोपसिंह लखावत की देखरेख में बनने वाले इस ऑडिटोरियम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि विद्यालय परिसर के विकास के लिए कई आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। परियोजना के अंतर्गत जोधपुरी पत्थर से विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण, मुख्य द्वार से ऑडिटोरियम तक फर्श निर्माण, समस्त दीवारों का प्लास्टर, कमरों के नए दरवाजे, आधुनिक सिलिंग, मां सरस्वती मंदिर का पुनर्निर्माण, अत्याधुनिक प्रकाश व्यवस्था एवं साउंड सिस्टम स्थापित किया जाएगा।

इसके अलावा बालिकाओं के लिए आवश्यक सुविधाओं का विस्तार, मंच का आधुनिकीकरण एवं विस्तार, मंच के पीछे की दीवार का पुनर्निर्माण तथा संपूर्ण फर्श पर मार्बल एवं ग्रेनाइट पत्थर लगाने का कार्य भी किया जाएगा। अनोपसिंह लखावत ने बताया कि विद्यालय में स्थित वर्तमान हॉल को आधुनिक स्वरूप देकर ह्यनिहाल ऑडिटोरियम में परिवर्तित किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों को शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं रचनात्मक गतिविधियों के लिए बेहतर मंच उपलब्ध होगा। ऑडिटोरियम में देश के स्वतंत्रता सेनानियों एवं महापुरुषों के थ्री-डी तकनीक से निर्मित चित्र लगाए जाएंगे, जिससे विद्यार्थियों को प्रेरणा प्राप्त होगी। इस अवसर पर चारण गढ़वी इंटरनेशनल फाउंडेशन के ग्लोबल अध्यक्ष अनोपसिंह लखावत, वरिष्ठ नागरिक समिति के अध्यक्ष सुरेश ओझा, प्रधानाचार्य स्वरूपसिंह उदावत, शिक्षाविद् सुरेंद्र कुमार व्यास, राजेन्द्र जोशी, डॉ. रशीद गौरी, धीरज गुप्ता सहित अनेक गणमान्यजन उपस्थित रहे।

सोजत: श्री वैधनाथ महादेव मंदिर में हुआ भव्य रुद्राभिषेक, जन्मदिवस पर समाजसेवी जोगेश जोशी का हुआ नागरिक अभिनंदन

सोजत। प्राचीन एवं ऐतिहासिक श्री वैधनाथ महादेव मंदिर में आयोजित रुद्राभिषेक कार्यक्रम में श्रद्धालुओं एवं गणमान्य नागरिकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। कार्यक्रम के यजमान पूर्व पार्षद जोगेश जोशी (लक्की जोशी) रहे, जिन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान महादेव का विधिवत अभिषेक एवं पूजा-अर्चना की। रुद्राभिषेक का आयोजन विद्वान पंडित सत्यनारायण अवस्थी एवं हरगोविंद अवस्थी के सान्निध्य में संपन्न हुआ। मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से सराबोर रहा तथा श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आराधना कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा गणमान्य नागरिकों ने पूर्व पार्षद और समाजसेवी जोगेश जोशी का साफा एवं माल्यार्पण कर स्वागत किया तथा उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं प्रेषित कीं। उपस्थित जनों ने उनके सामाजिक योगदान एवं जनसेवा की सराहना करते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान राजेश सिंह कच्छवाह,भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश पंवार,पाली जिला भाजपा उपाध्यक्ष नरपतराज सोलंकी, भाजपा नेता जुगल किशोर निकुंम, सहायक लोक अभियोजक पंकज त्रिवेदी, वरिष्ठ नागरिक समिति के हितेंद्र व्यास, अभिनव कला मंच के सचिव चेतन व्यास, प्रफुल्ल ओझा, अखिल भारतीय गुरु फूलनारायण आश्रम न्यास के अध्यक्ष सुरेंद्र त्रिवेदी, बुढ़ायत माता मंदिर व्यवस्था समिति के अध्यक्ष जितेंद्र व्यास,पूर्व पार्षद तरुण सोलंकी,भरत जोशी, रमेश व्यास, अशोक शर्मा, जितेंद्र श्रीमाली, अशोक बारहठ, संतोष सिंह, उम्मेद सिंह सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

ग्राम कचहरी प्रतिनिधि महासंघ एवं त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि महासंघ ने किया महाबैठक सह राज्य सम्मेलन का आयोजन

परिसीमन घोषित कर स्थानीय चुनाव कराये सरकार अन्यथा होगा आर पार की लड़ाई तेज

पटना। पंच सरपंच संघ, मुखिया संघ, जिला पार्षद संघ, प्रमुख संघ, वार्ड सदस्य संघ का संयुक्त संघ स्थानीय निकाय त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि महासंघ का महाबैठक सह राज्य सम्मेलन दरोगा राय ट्रस्ट भवन पटना के सभागार में आयोजित की गई। जिसकी अध्यक्षता मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश राय ने किया, वहीं सफल मंच संचालन पंच सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमोद कुमार निराला ने किया।

महाबैठक में राज्य भर के 500 प्रतिनिधि भाग लिये।

बैठक में स्थानीय निकाय के चुनाव पूर्व परिसीमन कर चुनाव कराने, आरक्षण रोस्टर तय करने, पंचायती राज आयोग का गठन करने, 2001 ई से पेंशन चालू करने, ओबीसी आयोग गठन करने, सम्मान सुरक्षा सुविधा वेतन बीमा भत्ता पेंशन अन्य अधिकार देने के सवाल पर गंभीर विस्तृत महाचर्चा किया गया।

बैठक में जिला पार्षद संघ के प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा कुमारी यादव, प्रमुख संघ के प्रदेश अध्यक्ष रश्मि कुमारी कार्यकारी अध्यक्ष जयमाला पासवान, वार्ड सदस्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी एवं महासंघ के राष्ट्रीय सचिव जवाहर राय सहित मोहम्मद अहसान, शेर सिंह, वशिष्ठ निषाद महेश राय, मुखिया संघ के खगड़िया जिला अध्यक्ष अनिल सिंह, आदि दर्जनों प्रतिनिधियों ने संबोधित किया।

पंच सरपंच संघ के खगड़िया जिला अध्यक्ष सह प्रदेश उपाध्यक्ष किरण देव यादव के लिखित प्रस्ताव को प्रदेश अध्यक्ष अमोद कुमार निराला ने रखते हुए कहा कि राज्यव्यापी असहयोग आंदोलन एवं चरणबद्ध आंदोलन किया जाय, जिसमें जून अंतिम सप्ताह में प्रखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन सभा करने, मध्य जुलाई में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन सभा करने तथा जुलाई अंतिम सप्ताह में पटना में मुख्यमंत्री के समक्ष रैली प्रदर्शन करने, राज्यस्तर पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाय, सभी जिला से स्मार पत्र सरकार को प्रेषित करने तथा 13 सूत्री प्रस्ताव पेश किया जिस पर बैठक में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों ने करतल ध्वनी से प्रस्ताव को पारित किया।

प्रतिनिधियों ने कहा कि परिसीमन के सवाल पर दायर याचिका पर हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद चुनाव आयोग एवं बिहार सरकार परिसीमन किए बगैर स्थानीय निकाय का चुनाव करना चाहती है जबकि परिसीमन किए 36 वर्ष गुजर चुका है। कई पंचायत एवं क्षेत्र नगर पंचायत नगर परिषद नगर निगम में कट चुका है। जिससे स्थानीय निकाय क्षेत्र प्रभावित हुई है। जिससे स्थानीय प्रतिनिधि एवं जनता विकास से वंचित है। यदि परिसीमन कर चुनाव कराई जाती है तो सीट एवं प्रतिनिधि बढ़ेगा तथा गांव का सरकार गांव में बनकर गांव का सर्वांगीण विकास करेगा। एवं महात्मा गांधी का सपना ग्राम स्वराज साकार होगा। प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार मांगे पूरी नहीं करेगी तो आर पार की लड़ाई तेज किया जाएगा।

बैठक में राजीव झा, मनोज सिंह, भागवत कुमार, भवेश सिंह, गुलाब यादव, विनोद यादव, क्रांति देवी, मधुकर कुमार, अभिषेक कुमार, कौशल कुमार, अमित सिंह, राजू राय आदि ने भाग लिया।

महासंघ (एकीकृत) की कर्मचारी जागृति यात्रा का शुभारंभ

जयपुर, 3 जून। राज्य कर्मचारियों के आत्म सम्मान एवं हितों की रक्षा करने के लिए अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के प्रदेश पदाधिकारियों की ओर से 8 जून से शुरू होने वाली कर्मचारी जागृति यात्रा का आज जयपुर में श्री गणेश हुआ। जागृति यात्रा आज महासंघ (एकीकृत) के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में गणेश मंदिर, मोती डूंगरी पहुंची और उनका आशीर्वाद लिया। कर्मचारी जागृति यात्रा के प्रस्थान पर महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों और 25 सूत्री लंबित मांगों की अनदेखी के विरोध में कर्मचारियों को जागृत करने के उद्देश्य से यह यात्रा प्रारंभ की जा रही है। राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने ढाई वर्ष के कार्यकाल में कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं किया है। चिंताजनक बात यह है कि राज्य सरकार अब वर्षों से चली आ रही राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) में सुधार करने के बजाय उसके निजीकरण की तैयारी में है। जिससे कर्मचारियों में काफी आक्रोश है। उन्होंने आगे बताया कि संवादहीनता के चलते कर्मचारियों की 25 सूत्री न्यायोचित मांगे भी लंबित हैं। राठौड़ के अनुसार कर्मचारी जागृति यात्रा का कार्यक्रम निम्न अनुसार रहेगा -8 जून को दौसा, अलवर और भरतपुर। 9 जून को धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। 10 जून को टोंक, बूंदी और कोटा। 11 जून को बारां और झालावाड़। 12 जून को भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। 13 जून को बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर। 14 जून को राजसमंद, ब्यावर और अजमेर। 17 जून को पाली सिरोही और जालौर। 18 जून को बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी। 19 जून को जोधपुर और नागौर। 23 जून को सीकर, झुंझुनू और चुरु। 24 जून को हनुमानगढ़ और गंगानगर। 25 जून को बीकानेर और डीडवाना।

'गवर्नर' की कहानी पर 5 साल तक चला शोध, विपुल शाह ने शुरूआत से ही मनोज बाजपेयी को माना था पहली पसंद

एक आइडिया से शुरू हुआ 'गवर्नर' का सफर, पांच साल की रिसर्च के बाद जानें कैसे बनी फिल्म

जित मुंबई: मनोज बाजपेयी और अदा शर्मा स्टारर फिल्म 'गवर्नर' को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। भारत के 1991 के आर्थिक संकट और उस दौर के अनसुने नायकों की कहानी को पर्दे पर लाने वाली इस फिल्म की शुरूआत एक दिलचस्प आइडिया से हुई थी। लेखक सुवेंदु भट्टाचार्य ने इस विषय को सबसे पहले सनशाइन पिक्चर्स के सामने रखा था। भारत के आर्थिक इतिहास के इस महत्वपूर्ण लेकिन कम चर्चित अध्याय ने निमार्ता विपुल अमृतलाल शाह को तुरंत प्रभावित किया और उन्होंने इसमें एक दमदार सिनेमाई कहानी की संभावनाएं देखीं।इसके बाद फिल्म की कहानी को विकसित करने का सफर शुरू हुआ, जो लगभग पांच वर्षों तक चला। इस दौरान सुवेंदु भट्टाचार्य और विपुल अमृतलाल शाह ने मिलकर कहानी की संरचना, स्क्रीनप्ले के विभिन्न ड्राफ्ट और 1990 के आर्थिक संकट के राजनीतिक, वित्तीय और भावनात्मक पहलुओं पर गहन काम किया। फिल्म को सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना तक सीमित न रखकर, उस दौर के मानवीय संघर्ष और फैसलों की गंभीरता को भी कहानी में पिरोने की कोशिश की गई।

बठिंडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 258 ग्राम हेरोइन, देसी रिवॉल्वर व 19 जिंदा कारतूस बरामद, चार आरोपी गिरफ्तार

बठिंडा, 3 जून (सुरेश रहेजा, परवीन कुमार, साहिल रहेजा)। पंजाब पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) **गौरव यादव, आईपीएस** तथा **डीआईजी बठिंडा रेंज हरजीत सिंह, आईपीएस** के दिशा-निर्देशों के तहत नशों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत बठिंडा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 258 ग्राम हेरोइन (चिट्टा), एक कार, एक देसी रिवॉल्वर तथा 19 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।

वरिष्ठ पुलिस कप्तान (एसएसपी) डॉ. ज्योति यादव, आईपीएस के नेतृत्व तथा **डीएसपी रामपुरा फूल मनोज कुमार, पीपीएस** की अगुवाई में थाना फूल पुलिस ने यह कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार थाना फूल में मुकदमा नंबर 75 दिनांक 1 जून 2026 को एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। जानकारी के अनुसार 1 जून को थाना फूल की पुलिस टीम गश्त और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच के लिए क्षेत्र में मौजूद थी। इसी दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध कार नंबर DL-9C-AA-2661 को रोककर उसकी तलाशी ली। कार में सवार तीन युवकों की पहचान अरमान सिंह पुत्र इकबाल सिंह निवासी कराईवाला जिला श्री मुक्तसर साहिब (उम्र लगभग 23 वर्ष), सतनाम सिंह उर्फ धर्मा पुत्र जगराज सिंह।

सुमेरपुर में सड़कों जाल होगा मजबूत, 13 सड़कों के लिए ?17 .50 करोड़ स्वीकृत

सुमेरपुर/पाली, 03 जून। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़क तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अनुशंषा पर सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने वर्ष 2026-27 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को गति देते हुए पाली जिले के सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। विभाग के संयुक्त सचिव (पथ) पंकज आर्य ने सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में 13 नॉन-पेचेबल (पूरी तरह क्षतिग्रस्त) सड़कों के नए सिरे से निर्माण के लिए 17.50 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है।

31 किलोमीटर से अधिक लंबा सड़क नेटवर्क होगा तैयार

स्थानीय विधायक और पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने बताया कि इस बजट राशि से सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों और ढाणियों को जोड़ने वाली कुल 31.70 किलोमीटर लंबी सड़कों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसके तहत पराखिया से बिरोलिया, दोलपुरा से खिमाड़ा, खिमाड़ा से राइकों की ढाणी, चाणोद से सिरवी घाट तक, जैतपुरा से डिंगाई तक, सापुनी खैरवा सड़क से मारू कुमावतों की ढाणी, मणिहारी से आशापुरा माता गोरी भाकरी वाला तक, भालेलाव से रीको तक, सापा से डीपीएस स्कूल तक, बल्दों की ढाणी से गाजनगढ तक, पाली खैरवा सड़क किमी. 11 से गुर्जरों की ढाणी तक, सोवनिया से हाईवे तक तथा डिंगाई से गुड़ा सोनीगरा तक नॉन पेचेबल सड़क का निर्माण किया जाएगा। ये वे सड़कें हैं जो लंबे समय से जर्जर अवस्था में थीं और पेचवर्क (पैच रिपेयरिंग) के जरिए ठीक होने की स्थिति में नहीं थीं। नई सड़कों के बनने से क्षेत्र में परिवहन सुगम होगा, वाहनों के रखरखाव का खर्च घटेगा और स्थानीय व्यापार को गति मिलेगी।

विकास की नई राह पर आगे बढ़ेगा सुमेरपुर : मंत्री कुमावत

मंत्री श्री कुमावत ने इस महत्वपूर्ण स्वीकृति पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने क्षेत्र की जनता की ओर से मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और सार्वजनिक निर्माण विभाग की मंत्री व उप-मुख्यमंत्री दीया कुमारी का विशेष आभार व्यक्त किया।

भारतीय संगीत की विलक्षण व्यक्तित्व प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा

डॉ उदय शंकर भगत

वाराणसी इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, क्षेत्रीय केन्द्र वाराणसी द्वारा भारतीय संगीत की प्रख्यात विदुशी प्रो0 प्रेमलता षर्मा जी की जन्मषताब्दी वर्श के उपलक्ष्य में 03 जून 2026 को प्रातः 10.30 बजे क्षेत्रीय केन्द्र वाराणसी सभागार में ग्रन्थ-लोकार्पण एवं परिचर्चा का आयोजन किया गया।

सर्वप्रथम स्मृतिशेष प्रो0 प्रेमलता षर्मा जी के चित्र पर उपस्थित विद्वानों द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गयी। तत्पश्चात क्षेत्रीय निदेशक डॉ0 अभिजित दीक्षित जी ने अतिथियों के लिये स्वागत भाशण प्रस्तुत कियाा और प्रो0 प्रेमलता षर्मा जी की व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाष डाला

तदुपरान्त इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के माननीय सदस्य सचिव डॉ सच्चिदानंद जोषी द्वारा मंचासीन अतिथ्यिों

को अंगवस्र एवं मोमेण्टो देकर सम्मानित किया गया।

तदनन्तर ग्रन्थ सम्मानीय सम्पादन प्रो कृश्णकान्त षर्मा ने विशय प्रवर्तन करते हुये प्रो प्रेमलता षर्मा जी के अथक परिश्रम एवं प्रयास को रेखांकित किया और राष्ट्रीय स्वयं स्वेवक संघ के कार्यकारिणी सदस्य माननीय सुरेश सोनी जी के प्रोत्साहन को स्मरण करते हुये कहा कि इस महत्त्वपूर्ण कार्य को यथाषीघ्र संपन्न करने हेतु सोनी जी ने हमें प्रेरित किया इसके बाद प्रेमलता श र्मा जी द्वारा लिखी गयी एवं प्रो कृश्णकान्त श र्मा जी के सम्पादकत्व तथा डॉ अभिजित दीक्षित एवं डॉ त्रिलोचन प्रधान जी के सह-सम्पादकत्व में सम्पादित की गयी ग्रन्थ संगीताध्याय के ह्यजातिविकल्पन-प्रथम पुश्पह्न का लोकार्पण अतिथियों द्वारा किया गया इसके बाद संगीत नाटक अकादेमी के निदेषिका मान्या डॉ0 सन्ध्या पुरेचा जी ने षुभाषंसा प्रस्तुत करते हुये प्रो0 प्रेमलता श र्मा जी के संगीत जगत के प्रति किये गये योगदान को स्मरण किया गया विषिश्ट अतिथि के रूप में उपस्थित काशी हिन्दूविष्वविद्यालय की संगीत एवं मंचकला संकाय की संकाय प्रमुख प्रो0 संगीता पण्डित ने अपने वक्तव्य में कहा कि संगीत जगत में इस प्रकार के षास्त्रीय कार्य अत्यन्त ही दुर्लभ है। नयी पीढी के विद्यार्थियों के लिये यह ग्रन्थ अत्यन्त ही उपयोगी है।

सारस्वत अतिथि के रूप में उपस्थित इन्दिरा कला एवं संगीत विष्वविद्यालय, खैरागड, के संगीत विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रो0 अनिल बिहारी ब्योहार ने प्रो0 प्रेमलता षर्मा जी की सान्निध्य का स्मरण करते हुये कहा कि जातिविकल्पन के अन्तर्गत विवेचित विशयों पर विस्तार से प्रकाष डाला इसके बाद सम्मान्य अतिथि, ध्रुपद घराने के विष्वविश्रुत विद्वान- पद्म श्री सम्मान से सम्मानित प्रो0 ऋत्विक सान्याल जी ने अपना मन्तव्य देते हुये कहा कि परम्परा की संरक्षण गुरूओं के सान्निध्य से ही सम्भव है। ध्रुवद गायकी सीखने के बाद काषी में प्रेमलता बहन से नाट्यषास्त्रीय सिद्धान्तों के अनुसार और संपुश्ट किया।

प्रधानमंत्री के अपमान के विरोध में भाजपा की विराट जन आक्रोश सभा

डॉ उदय शंकर भगत

वाराणसी आज दिनांक 03 जून 2026, बुधवार को प्रातः 09:00 बजे से 12:00 बजे तक कचहरी जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी महानगर एवं जिला द्वारा माननीय प्रधानमंत्री एवं काशी के सांसद नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय द्वारा की गई अशोभनीय एवं अमर्यादित टिप्पणियों के विरोध में एक विशाल आक्रोश सभा का आयोजन क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल की अध्यक्षता में किया गया सभा में उपस्थित हजारों भाजपा कार्यकताओं एवं पदाधिकारियों ने कांग्रेस नेतृत्व के विरुद्ध जोरदार विरोध दर्ज करते हुए प्रधानमंत्री के सम्मान में गगनभेदी नारे लगाए। पूरा जिला मुख्यालय प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान भारत माता की जय वंदे मातरम् और हर-हर महादेव के नारों से गुंजायमान रहा सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एवं प्रदेश अध्यक्ष अजय राय द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के विरुद्ध की गई अभद्र एवं अमर्यादित टिप्पणियां अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय एवं लोकतांत्रिक मयार्दाओं के विपरीत हैं। वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस अब सकारात्मक राजनीति की राह छोड़कर केवल व्यक्तिगत आरोपों और अपमानजनक भाषा का सहारा ले रही है। जनता ऐसे राजनीतिक आचरण को कभी स्वीकार नहीं करेगी और आने वाले समय में इसका करारा जवाब देगी वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जिससे विपक्ष पूरी तरह बौखला गया है। राजनीतिक पराजय और जनसमर्थन के अभाव से निराश विपक्ष अब मयार्दा की सभी सीमाएं लांघ रहा है। काशी की जनता अपने सांसद के सम्मान के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी सभा में कार्यकर्ता अपने हाथों में राहुल गांधी मुदार्बाद अजय राय होश में आओ प्रधानमंत्री का अपमान बंद करो आदि लिखी तख्तियां लेकर पहुंचे और कांग्रेस नेतृत्व के विरुद्ध अपना रोष व्यक्त किया सभा को संबोधित करने वाले प्रमुख लोगों में महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि, जिला अध्यक्ष राम सकल पटेल, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविंद्र जायसवाल, दयाशंकर मिश्र 'दयालु', महापौर अशोक तिवारी, हंसराज विश्वकर्मा, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, अवधेश सिंह, नीलकंठ तिवारी, विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्या, पूर्व सांसद राजेश मिश्रा, पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह औढ़े, प्रदेश मंत्री शंकर गिरी, मीना चौबे, प्रदेश प्रवक्ता अशोक पाण्डेय, विद्यासागर राय, प्रेम कपूर, पूर्व महापौर मृदुला जायसवाल, पूर्व विधान परिषद सदस्य वीणा पाण्डेय, डॉ. अशोक राय, अखिलेश सिंह सनी,शालिनी यादव, रचना अग्रवाल, गीता शास्त्री, चंद्रशेखर उपाध्याय, जगदीश त्रिपाठी, राहुल सिंह, सुधीर सिंह, सत्येंद्र सिंह पिंटू, अमित राय, दीपक राय, विभव सिंह, नितिन राय,रणजय सिंह , अवधेश राय, संजय कुमार, रत्नाकर राय,जे पी सिंह,हीरा यादव ,मनोज सोनकर ,रत्न मौर्य ,विनय सदेजा ,अंकित गौड़,बबलू अग्रहरि दिनेश यादव,प्रमील पाण्डेय सहित हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

बरेका में कर्मचारी हितों से जुड़े मुद्दों पर परिषद एवं प्रशासन के बीच सकारात्मक संवाद

डॉ उदय शंकर भगत

वाराणसी 'बनारस रेल इंजन कारखाना बरेका के प्रशासनिक भवन स्थित कीर्ति कक्ष में आज दिनांक 03 जून 2026 को प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर मनीष कुमार की अध्यक्षता में बरेका कर्मचारी परिषद एवं प्रशासन के मध्य एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सार्थक संवाद स्थापित कर उनके समाधान की दिशा में सकारात्मक पहल करना था बैठक के दौरान कर्मचारी परिषद द्वारा प्रस्तुत विभिन्न कर्मचारी कल्याण से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने परिषद के प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना तथा उनके व्यावहारिक एवं त्वरित समाधान हेतु सकारात्मक आश्वासन दिया

अध्यक्षीय संबोधन में प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर मनीष कुमार ने कहा कि कर्मचारियों का कल्याण एवं उनकी कार्यसंतुष्टि संस्थान की प्रगति का आधार है। उन्होंने प्रशासन एवं कर्मचारियों के मध्य निरंतर संवाद और सहयोग की भावना को और सुदृढ़ करने पर बल दिया बैठक में प्रधान वित्त सलाहकार मुक्तेश मित्तल, प्रमुख मुख्य इंजीनियर शैलेंद्र कुमार सिंह, प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी लालजी चौधरी, प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. देवेश कुमार तथा महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त देवराज कुमार मौर्य सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे कर्मचारी परिषद की ओर से संयुक्त सचिव प्रदीप कुमार यादव तथा परिषद के सदस्य अमित कुमार, नवीन कुमार सिन्हा, श्रीकांत यादव, सुशील कुमार सिंह संतोष कुमार यादव, धर्मेंद्र कुमार सिंह एवं मनीष कुमार सिंह ने सहभागिता की तथा कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न विषयों को प्रशासन के समक्ष रखा बैठक सौहार्दपूर्ण एवं सकारात्मक वातावरण में संपन्न हुई।

दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू के सम्मान में स्वागत समारोह आयोजित करेगा पीएचडीसीसीआई

-अमरपाल नूरपुरी

चंडीगढ़, 3 जून: पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) अपने पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ चैप्टर्स तथा रीजनल फैशन टेक्स टेक फोरम के माध्यम से 5 जून को चंडीगढ़ के हयात सेंट्रिक में दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल सरदार तरणजीत सिंह संधू के सम्मान में स्वागत समारोह आयोजित करेगा। इस अवसर पर ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथः विजन, इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा।

करण गिल्होत्रा, चेयर, पीएचडीसीसीआई पंजाब, ने कहा कि यह कार्यक्रम उद्योग और सरकार से जुड़े हितधारकों को नवाचार और विकास के मुद्दों पर विचार-विमर्श का मंच प्रदान करेगा। हिमानी अरोड़ा, चेयर, रीजनल फैशन टेक्स टेक फोरम, ने कहा कि यह आयोजन उद्योग और सरकार के बीच सहयोग को मजबूत करने की पीएचडीसीसीआई की प्रतिबद्धता को दशार्ता है। नवीन सेठ, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल, पीएचडीसीसीआई, ने कहा कि यह कार्यक्रम निवेश, नवाचार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सार्थक संवाद का अवसर प्रदान करेगा।

इफको के चेयरमैन दिलीप संघानी के नेतृत्व में भारत-अमेरिका कृषि सहयोग को मिली नई रफ्तार

चंडीगढ़ (अमरपाल नूरपुरी) : भारत और अमेरिका के बीच कृषि क्षेत्र में सहयोग को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से इफको के अध्यक्ष दिलीप संघाणी के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण संवाद आयोजित किया गया। वॉशिंगटन डी.सी. स्थित यू.एस.-इंडिया बिजनेस काउंसिल (यूएसआईबीसी) द्वारा पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) के प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की गई, जिसका नेतृत्व इफको अध्यक्ष दिलीप संघाणी कर रहे थे। बैठक के बाद यूएसआईबीसी ने इस संवाद को भारत-अमेरिका कृषि साझेदारी को नई दिशा देने वाली महत्वपूर्ण पहल बताया। यूएसआईबीसी ने अपने आधिकारिक संदेश में कहा कि दिलीप संघाणी के नेतृत्व में हुई चचाओं ने कृषि क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच सहयोग को नई ऊर्जा प्रदान करने, साझा चुनौतियों के समाधान खोजने तथा उभरते अवसरों पर सार्थक विचार-विमर्श का मार्ग प्रशस्त किया है।

चितकारा यूनिवर्सिटी में पंजाब का पहला आई.आर.एम. इंडिया एफिलिएट-लाइसेंस्ड ग्लोबल सेंटर फॉर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट किया लॉन्च

चंडीगढ़ , 3 जून, (अमरपाल नूरपुरी) : बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था, साइबर खतरों, जलवायु संकट और वित्तीय अनिश्चितताओं के दौर में जोखिम प्रबंधन (रिस्क मैनेजमेंट) की बढ़ती जरूरत को देखते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट (आई.आर.एम.) इंडिया एफिलिएट ने चितकारा यूनिवर्सिटी, पंजाब में एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट (ई.आर.एम.) का तीसरा ग्लोबल सेंटर स्थापित किया है। उत्तर भारत में अपनी तरह का यह महत्वपूर्ण केंद्र छात्रों और पेशेवरों को वैश्विक मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण और विशेषज्ञता प्रदान करेगा। सेंटर का उद्घाटन आई.आर.एम. इंडिया रीजनल ग्रुप के चेयरमैन एवं सी.?फ.आई.आर.एम. राजीव तन्ना ने किया। इस मौके पर आई.टी.सी. लिमिटेड के पूर्व चीफ रिस्क ऑफिसर संदीप दत्ता, चितकारा यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉ. अशोक के. चितकारा, वाइस चांसलर डॉ. संधीर शर्मा, आई.आर.एम. इंडिया एफिलिएट के सी.ई.ओ. हर्ष शाह सहित शिक्षा, उद्योग और प्रशासन जगत की कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं। आई.आर.एम. इंडिया एफिलिएट के गवर्नेंस बोर्ड सदस्य शैलेश हरिभक्ति भी ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े। पंजाब की उद्यमशीलता और नवाचार की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले इस केंद्र का उद्देश्य युवाओं को ऐसे कौशल प्रदान करना है, जिनकी जरूरत आज की जटिल और तेजी से बदलती दुनिया में महसूस की जा रही है। यहां विद्यार्थियों को वित्त, तकनीक, संचालन, गवर्नेंस और सस्टेनेबिलिटी जैसे क्षेत्रों में जोखिमों की पहचान और प्रबंधन की व्यावहारिक समझ विकसित करने का अवसर मिलेगा।

श्री सिद्ध बाबा बालक नाथ मंदिर, सेक्टर-29 में 52वां वार्षिक मूर्ति स्थापना उत्सव शुरू

चंडीगढ़, (अमरपाल नूरपुरी) सेक्टर-29 स्थित श्री सिद्ध बाबा बालक नाथ मंदिर में श्री सिद्ध बाबा बालक नाथ सेवा मंडल द्वारा 52वें वार्षिक मूर्ति स्थापना उत्सव का शुभारंभ श्रद्धा एवं भक्ति के साथ किया गया। यह धार्मिक आयोजन 7 जून तक चलेगा, जिसमें प्रतिदिन बाबा बालक नाथ जी की पूजा-अर्चना, भजन संध्याएं तथा विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

मूर्ति स्थापना उत्सव के प्रथम दिन भगवान श्री बाबा बालक नाथ जी की प्रतिमा का वैदिक मंत्रोच्चारण एवं पंचामृत स्नान के साथ विधि-विधानपूर्वक अभिषेक किया गया। इसके उपरांत धूना पूजन संपन्न हुआ तथा श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से बाबा जी की भव्य आरती में भाग लेकर सुख-समृद्धि और कल्याण की कामना की।

शाम को आयोजित भव्य भजन संध्या में प्रसिद्ध भजन गायक राजन राज एवं खुशप्रीत कौर ने बाबा बालक नाथ जी के सुंदर भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कलाकारों ने "पौणाहारिया सानूं प्यार तेरा चाहीदा", "रहमतां ने कीता ऐ कमाल जोगिया", "सोने दे सिंहासन ते आ के बह गए पौणाहारी", "तेरी मेहर जोगिया हो गई ऐ हुण मौजा ही मौजा" तथा "खाली न सानूं दरों मोड़ बाबा" सहित अनेक लोकप्रिय भजन प्रस्तुत किए। भजनों की मधुर प्रस्तुति पर श्रद्धालु भाव-विभोर होकर झूम उठे और पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से सराबोर हो गया।

बालेन्द्र शाह ने सीमा विवाद सुलझाने के लिए ब्रिटेन को निमंत्रित कर अपनी जगहँसाई करवा ली है

नीरज कुमार दुबे

हम आपको बता दें कि नेपाली संसद में बोलते हुए बालेन्द्र शाह ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री बनने के बाद पता चला कि केवल भारत ने ही नेपाल की जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि नेपाल ने भी कई स्थानों पर भारतीय भूमि पर अतिक्रमण किया है।

भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को लेकर चल रहा पुराना सीमा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह कोई नया भू-राजनीतिक घटनाक्रम नहीं बल्कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की चौंकाने वाली और कई मायनों में अपरिपक्व बयानबाजी बनी है। संसद में उन्होंने ऐसा दावा कर दिया जिसने काठमांडू से लेकर नई दिल्ली तक हलचल मचा दी। हालात इतने असहज हो गए कि कुछ ही घंटों बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय को सफाई देने मैदान में उतरना पड़ा। और विडंबना देखिए, भारत को घेरने की कोशिश में दिया गया बयान नेपाल में ही प्रधानमंत्री के लिए भारी पड़ गया। विपक्ष, पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व राजदूत और सीमा विशेषज्ञ तक उनके खिलाफ खड़े हो गए और उनसे सबूत, स्पष्टीकरण, यहां तक कि माफी की मांग होने लगी। सीमा विवाद पर राजनीतिक परिपक्वता दिखाने के बजाय बालेन्द्र शाह की टिप्पणियां ऐसी साबित हुईं जिन्होंने नेपाल की आधिकारिक स्थिति को ही कठघरे में खड़ा कर दिया।

हम आपको बता दें कि नेपाली संसद में बोलते हुए बालेन्द्र शाह ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री बनने के बाद पता चला कि केवल भारत ने ही नेपाल की जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि नेपाल ने भी कई स्थानों पर भारतीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। उन्होंने दोनों देशों से तथ्यों का अध्ययन कर मित्रवत तरीके से विवाद सुलझाने की अपील की। उधर, नेपाल में विपक्षी दलों और पूर्व राजनयिकों ने बालेन्द्र शाह की टिप्पणियों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। नेपाली कांग्रेस की बसना थापा और अन्य नेताओं ने संसद के अभिलेखों से बयान हटाने की मांग की। पूर्व विदेश मंत्री प्रदीप ज्ञवाली ने भी प्रधानमंत्री से माफी मांगने की बात कही। नेपाल के पूर्व राजदूत नीलाम्बर आचार्य और दीप कुमार उपाध्याय ने स्पष्ट कहा कि नेपाल द्वारा भारतीय भूमि पर अतिक्रमण का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। सीमा विशेषज्ञ बुद्धि नारायण श्रेष्ठ ने भी प्रधानमंत्री की बातों को तथ्यात्मक आधार से रहित बताया। इस प्रकार बालेन्द्र शाह का बयान भारत से अधिक नेपाल के भीतर ही विवाद का विषय बन गया।

दरअसल, सीमा विवाद का केंद्र लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्र हैं। नेपाल का दावा है कि सुगौली संधि के अनुसार काली नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा से होता है, इसलिए उसके पूर्व का पूरा क्षेत्र नेपाली भूभाग है। दूसरी ओर भारत का कहना है कि काली नदी का वास्तविक उद्गम लिपुलेख दर्रे के नीचे स्थित स्रोतों से होता है और ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार कालापानी क्षेत्र लंबे समय से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा रहा है। यही मूल विवाद दोनों देशों के दावों की जड़ में है।

हम आपको बता दें कि विवाद को हाल में उस समय नया मोड़ मिला जब नेपाल ने लिपुलेख मार्ग से होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आपत्ति जताते हुए भारत और चीन दोनों को कूटनीतिक नोट भेजा। भारत ने इस आपत्ति को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि लिपुलेख मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा 1954 से लगातार संचालित हो रही है और यह कोई नया घटनाक्रम नहीं है। भारत ने यह भी दोहराया कि एकतरफा तरीके से क्षेत्रीय दावों का विस्तार न तो ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है और न ही स्वीकार्य है।

उधर, बालेन्द्र शाह के बयान पर विवाद खड़ा होने के बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री का आशय यह नहीं था कि नेपाल ने आधिकारिक रूप से भारतीय भूमि पर कब्जा किया है। मंत्रालय के अनुसार सीमा के कुछ हिस्सों में सीमा स्तंभों की कमी, दशगजा क्षेत्र और सीमापार भूमि उपयोग जैसी व्यावहारिक समस्याओं के कारण ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं जहां दोनों ओर के लोग एक-दूसरे की जमीन का उपयोग करते रहे हैं। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने यह भी दोहराया कि दोनों देश कूटनीतिक बातचीत, तकनीकी सर्वेक्षण और ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

लेकिन सबसे अधिक हैरानी प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के उस सुझाव पर हुई जिसमें उन्होंने सीमा विवाद के समाधान में ब्रिटेन की भागीदारी की बात उठाई। उन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान सीमाओं की पृष्ठभूमि औपनिवेशिक काल से जुड़ी है, इसलिए ब्रिटेन को भी इस विषय में रुचि लेनी चाहिए। यह प्रस्ताव न केवल व्यावहारिक दृष्टि से कमजोर माना गया बल्कि नेपाल के भीतर भी इसे अपरिपक्व और अनावश्यक बताया गया। भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद हमेशा द्विपक्षीय ढांचे में चर्चा का विषय रहा है। ऐसे में तीसरे पक्ष को बीच में लाने की बात कूटनीतिक परंपराओं और स्थापित समझ से मेल नहीं खाती।

इसके अलावा, सीमा विवाद जैसे संवेदनशील और पूर्णतः द्विपक्षीय विषय में ब्रिटेन को शामिल करने का सुझाव बालेन्द्र शाह की कूटनीतिक नासमझी का ऐसा सार्वजनिक प्रदर्शन था जिसने कई जानकारों को हैरान कर दिया। भारत दशकों से स्पष्ट करता आया है कि वह अपने किसी भी द्विपक्षीय विवाद में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता या दखल को स्वीकार नहीं करता, चाहे मामला पाकिस्तान का हो, चीन का हो या नेपाल का। ऐसे में ब्रिटेन को बातचीत की मेज पर बुलाने का प्रस्ताव शुरू से ही अव्यावहारिक और वास्तविकताओं से कटा हुआ नजर आया। जिस देश ने दो शताब्दियों पहले उपमहाद्वीप छोड़ दिया, उसे आज की सीमा वाताओं में घसीटने की कोशिश को कई पर्यवेक्षकों ने राजनीतिक अपरिपक्वता बताया। दिलचस्प यह है कि बालेन्द्र शाह की इस टिप्पणी पर केवल नेपाल में ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन के रणनीतिक और दक्षिण एशियाई मामलों पर नजर रखने वाले हलकों में भी हैरानी जताई गई और इसे अव्यावहारिक सोच का उदाहरण माना गया। कूटनीति की दुनिया में जहां गंभीरता, तैयारी और यथार्थवादी दृष्टिकोण की अपेक्षा की जाती है, वहां बालेन्द्र शाह का यह सुझाव कई लोगों को ऐसा लगा मानो किसी जटिल अंतरराष्ट्रीय विवाद के समाधान के लिए इतिहास की धूल झाड़कर ऐसे पात्रों को मंच पर बुलाने की कोशिश की जा रही हो जिनकी अब उस प्रक्रिया में कोई वास्तविक भूमिका ही नहीं बची है।

देखा जाये तो सामरिक दृष्टि से लिपुलेख क्षेत्र का महत्व अत्यंत गहरा है। यह भारत, नेपाल और चीन के त्रिसीमा क्षेत्र के निकट स्थित है। यह केवल धार्मिक यात्रा का मार्ग नहीं बल्कि हिमालयी क्षेत्र में संपर्क, निगरानी और रणनीतिक पहुंच का महत्वपूर्ण केंद्र भी है। चीन की बढ़ती सक्रियता और हिमालयी क्षेत्र में बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों के बीच यह इलाका राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से और भी संवेदनशील हो गया है। इसलिए इस क्षेत्र से जुड़ा कोई भी राजनीतिक बयान केवल घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं रहता बल्कि उसके व्यापक सामरिक प्रभाव भी होते हैं।

नेपाल के प्रधानमंत्री का बयान इसी कारण अधिक विवादास्पद बन गया। बिना पर्याप्त तैयारी और तथ्यों की मजबूत प्रस्तुति के ऐसे संवेदनशील विषयों पर टिप्पणी करना न केवल कूटनीतिक भ्रम पैदा करता है बल्कि अपने ही देश की आधिकारिक स्थिति को कमजोर भी कर सकता है। यही कारण है कि उनकी टिप्पणियों के तुरंत बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय को स्पष्टीकरण देना पड़ा और देश के अनेक राजनीतिक तथा कूटनीतिक विशेषज्ञों ने उनकी आलोचना की।

बहरहाल, यह पूरा प्रकरण एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। भारत और नेपाल के बीच सीमा से जुड़े मतभेद अवश्य हैं, लेकिन दोनों देशों ने बार-बार बातचीत और कूटनीति के माध्यम से समाधान की प्रतिबद्धता जताई है। ऐसे समय में भावनात्मक या बचकाने राजनीतिक बयान समाधान का रास्ता नहीं खोलते, बल्कि अनावश्यक भ्रम और विवाद को जन्म देते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की हालिया टिप्पणियां इसी का उदाहरण बन गई हैं, जहां भारत पर निशाना साधने की कोशिश से अधिक नुकसान उन्हें अपने ही देश के राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में उठाना पड़ा है।

संपादकीय

विराट और वैभव

भले ही फटाफट क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाला आईपीएल बाजार और नई पीढ़ी के जुनून का संगम हो, लेकिन लोकप्रियता के नये आयाम तय करता यह खेल अब दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों की पहली पसंद बन गया है। इस बार इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे चमकीले सितारे बनकर उभरे टी-20 सनसनी वैभव सूर्यवंशी। महज पंद्रह साल की उम्र में उनकी कामयाबी हैरत में डालने वाली है। वहीं अनुभवी क्रिकेटर विराट कोहली ने अपने खास अंदाज में सबका ध्यान आकर्षित किया। इस 37 वर्षीय दिग्गज क्रिकेटर ने फाइनल में तूफानी अर्धशतक लगाकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी को लगातार दूसरी बार ट्राफी दिलाई। दो महीने तक चले इस टूर्नामेंट में कोहली की फॉर्म और फिटनेस शानदार रही है। यही वजह है कि वर्ष 2027 एकदिवसीय क्रिकेट के विश्व कप में उनकी भागीदारी अब लगभग तय लग रही है। खुद कोहली ने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्हें अपनी मनःस्थिति में बदलाव लाने और युवा खिलाड़ियों से थोड़ा सीखने की जरूरत थी, ताकि वे टी-20 क्रिकेट में अपने खेल को नये सिरे से निखार सकें। यह सुखद ही है कि इस दिग्गज क्रिकेटर की यह ईमानदार स्वीकारोक्ति भारतीय क्रिकेट को आकार दे रही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की खूबसूरत बानगी को ही दशार्ती है। निस्संदेह, हाल ही में संपन्न हुए इंडियन प्रीमियर लीग सीजन ने साफ दिखाया कि दो पीढ़ियों के क्रिकेटर कैसे एक-दूसरे के पूरक भी हो सकते हैं। वास्तव में, विराट कोहली आज भी एक प्रभावशाली खिलाड़ी की छवि को बनाये हुए हैं। वहीं वैभव सूर्यवंशी जैसे उदीयमान खिलाड़ी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस फटाफट क्रिकेट में खेल का निरंतर विकास होता रहेगा। यह सुखद ही है कि राजस्थान रॉयल्स के इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी सूर्यवंशी ने अधिकांश पुरस्कार अपने नाम किए हैं। मसलन मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, सुपर स्ट्राइक ऑफ द सीजन, ऑरेंज कैप विजेता और सुपर सिक्स ऑफ द सीजन जैसे खिताब हासिल किए।

चिंतन-मनन

सच्चा मित्र संजीवनी की तरह

हम सभी के परिचित और दोस्त होते हैं। भले ही बचपन के, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या आस-पास कॉलोनी में रहने वाले हों, मित्र तो सभी के होते हैं। सच्चा मित्र बनना और बनाना हर इंसान की इच्छा होती है। लेकिन, सच्चे मित्र बहुत कम मिल पाते हैं। ऐसा मित्र, जिस पर हम भरोसा कर सकें, जिसके साथ अपनी हर बाते शेयर कर सकें। धर्मशास्त्रों में सच्चा मित्र उसे कहा गया है, जो सुख-दुख में साथ दे। ऐसे दोस्त से कभी भी डर नहीं लगता। ये सही रास्ते पर चलने में हमारे मददगार होते हैं। लेकिन, ऐसा दोस्त कौन है? क्या वह जो सिर्फ परिचित है? सच्ची दोस्ती प्रेम, विश्वास व भरोसा, एक-दूसरे का ख्याल रखने और चिंताओं पर ही आधारित होती है। क्या, कभी इस प्रश्न का उत्तर आपने खुद से पूछा है?

प्रिय शब्दों से मित्रों की संख्या बढ़ती है और मधुर वाणी से मैत्रीपूर्ण व्यवहार। हमारे परिचित अनेक हों, किंतु परामर्शदाता ईश्वर एक ही है। ईश्वर ही सच्चा दोस्त है, जो जीवन के हर पल में हमारी परछाई बनकर साथ रहता है। उस पर अपनी आंखें बंद कर, विश्वास व भरोसा करते हैं। जब सुखी या दुखी होते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के रूप में उससे बातें करते हैं। जीवन की हर बात उससे साझा करते हैं और फिर खुद को हल्का महसूस करते हैं। किसी भी कार्य की शुरूआत हम ईश्वर से आशीर्वाद लेकर ही करते हुए कहते हैं-हे मेरे मालिक, मुझ पर अपनी छत्र-छाया बनाए रख, मेरा मार्गदर्शन कर और मुझे सफलता प्रदान कर।

कोई मित्र अवसरवादी होता है, वह विपत्ति में साथ नहीं देगा। कोई मित्र शत्रु बन जाता है और अलगाव का दोष भी हमें ही देता है। कोई मित्र हमारे यहां खाता-पीता है, किंतु विपत्ति के वक्ति दिखाई नहीं देता। समृद्धि के दिनों में वह हमारा अंतरंग बन कर रौब जमाता है, किंतु दुर्दिन आते ही शत्रु बनकर मुंह फेर लेता है। परीक्षा लेने के बाद किसी को मित्र बना लो, लेकिन उस पर तुरंत विश्वास मत करो। अपमान, अहंकार और विश्वासघात के कारण मित्रता टूट जाती है। कभी ऐसा भी होता है, जिस दोस्त पर हम सबसे ज्यादा विश्वास व भरोसा करते हैं, वही विश्वासघात करता है और हृदय पर चोट लगने पर मित्रता टूट जाती है।

अगर, हम संकट और दरिद्रता में मित्र का साथ दें तो उसकी समृद्धि और विरासत के साझेदार बन सकते हैं। सच्चा दोस्त जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उससे घर-परिवार व समाज में पहचान बनती है। सच्चा मित्र प्रबल सहायक है। जिसे मिल जाता है, समझो उसे खजाना मिल गया। ऐसे मित्र की कीमत धन से नहीं चुकाई जा सकती। सच्चा मित्र असल में संजीवनी है। इंसान जैसा है, उसका मित्र भी वैसा ही होगा।

विश्व साइकिल दिवसः प्रदूषण पर भाषण बहुत हुए, अब घर के कोने से साइकिल निकालिए

दिलीप कुमार पाठक

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब हर व्यक्ति समय की कमी और तनाव की शिकायत करता है, तब एक बेहद साधारण और किफायती समाधान हमारे सामने खड़ा दिखाई देता है। वह समाधान है - साइकिल। आज 3 जून को पूरी दुनिया विश्व साइकिल दिवस मना रही है। यह दिन किसी आधुनिक आविष्कार का जश्न नहीं, बल्कि उस सादगी और उपयोगिता को याद करने का अवसर है, जिसे हमने विकास की अंधी दौड़ में कहीं पीछे छोड़ दिया है। जब पूरी दुनिया महंगे ईंधन, ट्रैफिक जाम और जहरीले धुएं से हांफ रही है, तब साइकिल एक सुगम साधन की तरह नजर आती है। यह कोई साधारण सवारी नहीं, बल्कि बिना धुएं वाली वह मूक क्रांति है जो व्यक्ति की सेहत, जेब और धरती तीनों को एक साथ संवार सकती है।

आजकल की जीवनशैली को देखें तो हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आती हैं। घर से महज दो कदम दूर सब्जी की दुकान या दूध की डेयरी तक जाने के लिए भी लोग तुरंत मोटरसाइकिल या कार की चाबी उठा लेते हैं। नतीजा यह हुआ है कि शहरों की हवा भारी हो चुकी है, सड़कों पर पैदल चलने की जगह नहीं बची और इंसानी शरीर बीमारियों का घर बनता जा रहा है। लोग शारीरिक रूप से खुद को फिट रखने के लिए हर महीने जिम में हजारों रुपये खर्च करते हैं और एक ही जगह खड़े होकर ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं। जबकि इसका सबसे आसान और प्राकृतिक विकल्प हमारी दिनचर्या में ही छुपा है। सुबह या शाम को सिर्फ आधा घंटा साइकिल चलाना दिल को मजबूत करता है, मानसिक तनाव को कम करता है और शरीर को ऊर्जा से भर देता है।साइकिल की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह समाज में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करती। इसके लिए न तो महंगे पेट्रोल-डीजल की जरूरत होती है और न ही किसी भारी-भरकम मेंटेनेंस या सर्विसिंग के खर्च की। यह आत्मनिर्भरता और बचत का सबसे पहला और सच्चा पाठ पढ़ाती है। आज जब ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याएं पूरी दुनिया के लिए चुनौती बनी हुई हैं, तब साइकिल जमीन पर उतरकर इसका व्यावहारिक समाधान देती है। अगर किसी भी शहर का हर तीसरा व्यक्ति अपने छोटे-मोटे स्थानीय कामों के लिए गाड़ियों को छोड़कर साइकिल का इस्तेमाल करना शुरू कर दे, तो वायु प्रदूषण और ट्रैफिक की समस्या काफी हद तक हल हो सकती है।कई विकसित देशों ने इस बात को गहराई से समझा है और साइकिल को अपनी मुख्य जीवनशैली का हिस्सा बनाया है। वहाँ बड़े-बड़े अधिकारी और सजग नागरिक गर्व से साइकिल से दफ्तर जाते हैं। हमारे देश में भी अब धीरे-धीरे जागरूकता बढ़ रही है और शहरों में साइकिलिंग ग्रुप्स का चलन देखने को मिल रहा है। हालांकि, इस बदलाव को एक राष्ट्रव्यापी मुहिम बनाने के लिए हमें अपनी मानसिकता और बुनियादी ढांचे दोनों में सुधार करना होगा। आज भी हमारे शहरों की सड़कें सिर्फ बड़ी और तेज रफ्तार गाड़ियों के हिसाब से बनाई जाती हैं। साइकिल चालकों के लिए अलग सुरक्षित लेन न होने के कारण लोग सड़कों पर निकलने से कतराते हैं। सरकारों को शहरी नियोजन में साइकिल ट्रैक को प्राथमिकता देनी होगी।इसके साथ ही, समाज को इस संकुचित सोच से भी बाहर निकलना होगा कि साइकिल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो गाड़ी नहीं खरीद सकते। साइकिल चलाना पिछड़ेपन की नहीं, बल्कि एक बेहद जागरूक, समझदार और आधुनिक नागरिक होने की पहचान है। इस विश्व साइकिल दिवस पर हमें केवल औपचारिक संदेश भेजने के बजाय एक छोटा सा व्यावहारिक संकल्प लेना चाहिए। तय करें कि सप्ताह में कम से कम एक या दो दिन हम अपनी गाड़ियों को आराम देंगे और नजदीकी कामों के लिए साइकिल की सवारी करेंगे। जब आपकी साइकिल का पहिया घूमता है, तो देश की सेहत और पर्यावरण का पहिया भी सही दिशा में आगे बढ़ता है।

क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता कोरा बुलबुला है या वास्तविक चुनौती?

ललित गर्ग

मानव सभ्यता के इतिहास में कुछ ऐसी क्रांतियां हुई हैं जिन्होंने जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल दिया। कृषि क्रांति ने मनुष्य को स्थायित्व दिया, औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन और श्रम की परिभाषा बदली, सूचना क्रांति ने ज्ञान और संचार की सीमाएं समाप्त कर दीं। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई की क्रांति मानव इतिहास के एक नए मोड़ पर खड़ी है। यह केवल एक तकनीकी परिवर्तन नहीं है, बल्कि मनुष्य की बुद्धि, निर्णय क्षमता, रोजगार, सामाजिक संरचना, शासन व्यवस्था और यहां तक कि उसके अस्तित्व और अस्मिता से जुड़ा प्रश्न बन चुकी है। यही कारण है कि आज विश्वभर में यह बहस तेज हो रही है कि क्या एआई मानव जीवन के लिए वरदान सिद्ध होगी या वह धीरे-धीरे मनुष्य के महत्व को ही चुनौती देने लगेगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल मशीनों को चलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह उन कार्यों को भी करने लगी है जिन्हें लंबे समय तक केवल मनुष्य की विशिष्ट क्षमता माना जाता था। लेखन, चित्र निर्माण, संगीत रचना, रोगों का निदान, न्यायिक विश्लेषण, वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रशासनिक निर्णय जैसे क्षेत्रों में इसकी बढ़ती उपस्थिति ने अनेक नए प्रश्न खड़े कर दिए हैं। यदि मशीनें सोचने, सीखने और निर्णय लेने लगेंगी तो मनुष्य की विशिष्टता क्या रह जाएगी? यह प्रश्न केवल तकनीकी नहीं, बल्कि दार्शनिक और नैतिक भी है।

मानव अस्मिता का आधार उसकी चेतना, संवेदना, रचनात्मकता और नैतिक विवेक है। एआई के पास विशाल सूचनाओं का भंडार और तीव्र गणनात्मक क्षमता अवश्य है, लेकिन उसके पास अनुभवजन्य चेतना, करुणा, आत्मबोध और मूल्यबोध नहीं है। फिर भी जब मशीनें कविता लिखती हैं, चित्र बनाती हैं और संवाद करती हैं, तब यह भ्रम उत्पन्न होने लगता है कि वे मनुष्य का स्थान ले सकती हैं। वास्तव में चुनौती यह नहीं है कि मशीनें मनुष्य बन जाएंगी, बल्कि यह है कि कहीं मनुष्य स्वयं मशीनों की तरह व्यवहार करने न लगे। यदि जीवन का प्रत्येक निर्णय गणनात्मक दक्षता और आंकड़ों के आधार पर होने लगे, तो मानवीय संवेदनाएं और नैतिक मूल्य हाशिये पर जा सकते हैं। इसी संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उभरता है कि क्या भविष्य में एक नई मानव संरचना का निर्माण होगा? विश्व के अनेक वैज्ञानिक और तकनीकी चिंतक यह मानते हैं कि आने वाले दशकों में जैविक मनुष्य और डिजिटल तकनीक के बीच की दूरी लगातार कम होगी। मस्तिष्क और कंप्यूटर के प्रत्यक्ष संपर्क, कृत्रिम अंगों, स्मृति-विस्तार तकनीकों और जैव-तकनीकी हस्तक्षेपों के माध्यम से एक ऐसे युग की कल्पना की जा रही है जहां मनुष्य और मशीन का सम्मिलित स्वरूप विकसित हो सकता है। यह संभावना जितनी आकर्षक दिखाई देती है, उतनी ही चिंताजनक भी है। यदि तकनीकी रूप से उन्नत मनुष्य और सामान्य मनुष्य के बीच गहरी खाई बन गई तो सामाजिक असमानता का एक नया रूप सामने आ सकता है।

एआई के बढ़ते प्रभाव के साथ रोजगार और अर्थव्यवस्था में भी व्यापक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। अनेक क्षेत्रों में नियमित और दोहराव वाले कार्य मशीनों द्वारा किए जाने लगे हैं। इससे यह आशंका उत्पन्न हुई कि बड़ी संख्या में रोजगार समाप्त हो जाएंगे। विश्व की कई बड़ी तकनीकी कंपनियों ने लागत कम करने और उत्पादकता बढ़ाने के नाम पर कर्मचारियों की संख्या घटाई है। किंतु हाल के अनुभव यह भी बताते हैं कि एआई मानव श्रम का पूर्ण विकल्प नहीं बन सकी है। जटिल निर्णय, नवाचार, मानवीय संबंधों का प्रबंधन और परिस्थितिजन्य विवेक जैसे क्षेत्रों में मनुष्य की भूमिका अभी भी केंद्रीय बनी हुई है। यहीं पर वैश्विक शोध संस्था गार्टनर की हालिया रिपोर्ट विशेष महत्व रखती है। गार्टनर ने अपनी नवीनतम विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में संकेत दिया है कि एआई अब अत्यधिक अपेक्षाओं के शिखर से आगे बढ़कर मोहभंग के चरण में प्रवेश कर रही है। अनेक कंपनियों ने इससे तत्काल आर्थिक लाभ और उत्पादकता में चमत्कारी वृद्धि की उम्मीद की थी, लेकिन वास्तविक परिणाम अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं मिले। परियोजनाओं की ऊंची लागत, आंकड़ों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं, गलत या भ्रामक उत्तर देने की प्रवृत्ति और स्पष्ट उपयोगिता सिद्ध न कर पाने जैसी समस्याएं सामने आई हैं। रिपोर्ट में यह आशंका भी व्यक्त की गई है कि लगभग एक-तिहाई परियोजनाएं प्रारंभिक चरण के बाद बंद हो सकती हैं क्योंकि वे अपने निवेश के अनुरूप परिणाम देने में असफल रही हैं। यह निष्कर्ष इस धारणा को चुनौती देता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता तत्काल सभी समस्याओं का समाधान बन जाएगी।

हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि एआई एक अस्थायी बुलबुला है जो शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। इतिहास बताता है कि हर बड़ी तकनीकी क्रांति के प्रारंभिक चरण में उत्साह और अतिशयोक्ति दोनों मौजूद रहते हैं। बाद में वास्तविक उपयोगिता के आधार पर उसका संतुलित विकास होता है। इंटरनेट के साथ भी यही हुआ था। प्रारंभिक उत्साह के बाद अनेक कंपनियां समाप्त हो गईं, लेकिन इंटरनेट स्वयं विश्व व्यवस्था का आधार बन गया। एआई के साथ भी कुछ ऐसा ही होने की संभावना है। अतः इसका अतिशयोक्तिपूर्ण महिमामंडन भी उचित नहीं है और इसके शीघ्र समाप्त हो जाने की कल्पना भी यथार्थवादी नहीं है। व्यापार जगत में एआई की भूमिका निरंतर बढ़ेगी। उत्पादन, विपणन, ग्राहक सेवा, वित्तीय विश्लेषण और आपूर्ति प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में इसका व्यापक उपयोग होगा। इससे कार्यों की गति और दक्षता बढ़ेगी, किंतु साथ ही कार्यबल के स्वरूप में परिवर्तन आएगा। भविष्य में केवल तकनीकी ज्ञान पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि समस्या समाधान, रचनात्मकता, नेतृत्व क्षमता और भावनात्मक समझ जैसे गुण अधिक महत्वपूर्ण बनेंगे। इसलिए शिक्षा और कौशल विकास की पूरी व्यवस्था को नए सिरे से तैयार करना होगा। प्रशासनिक क्षेत्र में भी एआई शासन को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने की क्षमता रखती है। नीतिगत विश्लेषण, संसाधनों का वितरण, स्वास्थ्य और शिक्षा योजनाओं का संचालन तथा आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में इसका उपयोग लाभकारी हो सकता है। लेकिन इसके साथ एक बड़ा खतरा भी जुड़ा है। यदि नागरिकों के व्यक्तिगत आंकड़ों का अत्यधिक संग्रह और विश्लेषण होने लगे तो निजता और स्वतंत्रता पर गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। इसलिए तकनीकी दक्षता और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होगा। सैन्य क्षेत्र में एआई का प्रयोग सबसे अधिक चिंताजनक माना जा रहा है। स्वायत्त हथियार प्रणालियां, मानव रहित युद्धक उपकरण और लक्ष्य चयन करने वाली मशीनें युद्ध की प्रकृति को पूरी तरह बदल सकती हैं। यदि किसी मशीन को जीवन और मृत्यु का निर्णय करने की शक्ति मिल जाए तो नैतिक और मानवीय प्रश्न अत्यंत गंभीर हो जाएंगे। इसलिए विश्व स्तर पर ऐसी तकनीकों के नियमन और नियंत्रण की आवश्यकता लगातार महसूस की जा रही है।

इन सबके बीच सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि मानव जीवन सुरक्षित, संतुलित और सार्थक कैसे बना रहे? इसका उत्तर तकनीक के विरोध में नहीं, बल्कि उसके विवेकपूर्ण उपयोग में निहित है। एआई को मानव जीवन का स्वामी नहीं, सहायक बनाना होगा। शिक्षा प्रणाली में नैतिकता, संवेदनशीलता, सह-अस्तित्व और मानवीय मूल्यों को अधिक महत्व देना होगा। मनुष्य की भावनात्मक बुद्धिमत्ता, करुणा, सहानुभूति और आध्यात्मिक चेतना ही वे क्षेत्र हैं जिन्हें कोई मशीन प्रतिस्थापित नहीं कर सकती। साथ ही, वैश्विक स्तर पर ऐसे नियमों और नीतियों की आवश्यकता है जो एआई के विकास को मानव कल्याण की दिशा में नियंत्रित करें। यदि यह तकनीक केवल कुछ शक्तिशाली कंपनियों या राष्ट्रों के हितों तक सीमित रह गई तो असमानता और संघर्ष बढ़ सकते हैं। इसके विपरीत यदि इसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक विकास के लिए किया जाए तो यह मानवता के लिए अभूतपूर्व अवसरों का द्वार खोल सकती है।

अंततः एआई न तो पूर्णतः वरदान है और न ही अनिवार्य रूप से अभिशाप। यह एक शक्तिशाली साधन है जिसकी दिशा और परिणाम मनुष्य के विवेक पर निर्भर करेंगे। चुनौती मशीनों से नहीं, बल्कि इस बात से है कि क्या मनुष्य अपनी मानवीयता, संवेदनशीलता और नैतिक चेतना को सुरक्षित रख पाएगा। भविष्य का प्रश्न यह नहीं है कि एआई कितनी शक्तिशाली होगी, बल्कि यह है कि मनुष्य कितना सजग, उत्तरदायी और मूल्यनिष्ठ बना रहेगा। यदि मानवता तकनीकी प्रगति और मानवीय मूल्यों के बीच संतुलन स्थापित कर सकी, तो एआई मानव विकास का नया अध्याय लिखेगी अन्यथा वही तकनीक असंतुलन, असमानता और अस्तित्वगत संकट का कारण भी बन सकती है। यही हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

विनिर्माण तीन महीने के उच्चतम पर, राजकोषीय घाटा लक्ष्य हासिल

नई दिल्ली ।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मई 2026 सकारात्मक रहा, विनिर्माण गतिविधियां तीन महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं, वहीं सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को भी सफलतापूर्वक हासिल कर लिया। एचएसबीसी इंडिया विनिर्माण खरीद प्रबंधन सूचकांक (पीएमआई) मई में 55 पर पहुंच गया, जो मजबूत घरेलू मांग, नए ऑर्डरों और बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च का परिणाम है। कच्चे तेल में उछाल के कारण उपजी लागत के दबाव के बावजूद कंपनियों ने उत्पादन और कच्चे माल की खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि की। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में 4.4 फीसदी के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया। संशोधित आंकड़ों के अनुसार यह घाटा 15,58,492 करोड़ रुपये रहा, जबकि इस दौरान कुल राजस्व संग्रह 33.42 लाख करोड़ रुपये रहा। हालांकि, बिजली की मांग बढ़ने के बावजूद कोल इंडिया का कोयला उत्पादन मई, 2026 में 5.61 करोड़ टन रहा। अप्रैल-मई की अवधि में कंपनी का कुल उत्पादन 10.6 फीसदी घट गया, जिसकी वजह कंपनी ने नहीं बताई।

सीएसपीटीसीएल आईपीओ की राह पर, आम निवेशकों के लिए खुलेंगे द्वार

रायपुर ।

छत्तीसगढ़ पावर ट्रांसमिशन कंपनी (सीएसपीटीसीएल) जल्द ही अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) लाने की तैयारी में है। इसके जरिए कंपनी आम निवेशकों से पूंजी जुटाएगी। यह कदम सफल होने पर सीएसपीटीसीएल राज्य सरकार की पहली ऐसी कंपनी बन जाएगी, जिसके शेयर स्टॉक मार्केट में कारोबार के लिए उपलब्ध होंगे। आईपीओ का उद्देश्य कंपनी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना, निवेशकों का व्यापक आधार तैयार करना और पूंजी जुटाना है। इसके बाद कंपनी के शेयर शेयर बाजार में सूचीबद्ध होंगे, जिससे आम नागरिक भी कंपनी के विकास में भागीदार बन सकेंगे और मुनाफे पर लाभांश प्राप्त कर सकेंगे। कंपनी के एक अे धिकारी ने बताया कि देश की कई सरकारी और केंद्रीय ऊर्जा कंपनियां पहले से ही आईपीओ के जरिए पूंजी जुटा रही हैं। उन्होंने पुष्टि की कि छत्तीसगढ़ ट्रांसमिशन कंपनी के आईपीओ लाने पर उच्च स्तर पर चर्चा चल रही है, जो शासन स्तर का मामला है। गौरतलब है कि पूर्व में छत्तीसगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बॉन्ड जारी किए थे, पर उसके शेयरों में कारोबार नहीं होता।

रुपया 16 पैसे चढ़कर 95.03 प्रति डॉलर पर खुला

रुपया सोमवार को 34 पैसे टूटकर 95.19 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था

मुंबई ।

रुपया मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले शुरुआती कारोबार में 16 पैसे मजबूत होकर 95.03 पर पहुंच गया। भारत की मजबूत घरेलू आर्थिक स्थिति और जारी भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच संतुलन बनने से रुपये को समर्थन मिला। विदेशी मुद्रा कारोबारियों का कहना है कि पश्चिम एशिया की अनिश्चित स्थिति हालांकि अब भी वित्तीय बाजारों और ऊर्जा कीमतों पर दबाव बनाए हुए है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 95.16 प्रति डॉलर पर खुला। शुरुआती कारोबार में चढ़कर 95.03 प्रति डॉलर तक पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से 16 पैसे अधिक है। रुपया सोमवार को 34 पैसे टूटकर 95.19 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.01 प्रतिशत की गिरावट के साथ 99.19 पर रहा।

आरबीआई जून एमपीसी में रेपो रेट को रख सकता है स्थिर, आउटलुक और आक्रामक होने की उम्मीद- एचएसबीसी

नई दिल्ली।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) आने वाली जून मौद्रिक नीति कमेटी (एमसीसी) में रेपो रेट को स्थिर रख सकता है। वहीं, कमजोर रुपया और कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के कारण महंगाई में इजाफा होने की संभावना के चलते आउटलुक और अधिक आक्रामक होने की उम्मीद है। यह बयान एचएसबीसी में एक अर्थशास्त्री की ओर से दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एचएसबीसी की चीफ इंडिया इकोनॉमिस्ट और मैक्रो स्ट्रैटजिस्ट प्रांजुल भंडारी का कहा कि इस मौद्रिक नीति में आरबीआई का महंगाई और अर्थव्यवस्था की विकास दर को लेकर आने वाला अनुमान बताएगा कि नीति निर्माता कैसे इस ऊर्जा संकट को देख रहे हैं।

पिछले रिव्यू में केंद्रीय बैंक ने तेल की आधारभूत कीमत लगभग 85 डॉलर प्रति बैरल और वैकल्पिक परिदृश्य के रूप में 95 डॉलर का उपयोग किया था। एचएसबीसी की अर्थशास्त्री का मानना है कि तेल की ऊंची कीमतों का अनुमान अब आरबीआई का आधार होगा, जिससे महंगाई का अनुमान पहले के 4.6 प्रतिशत के अनुमान से बढ़कर 5 प्रतिशत के करीब पहुंच जाएगा। भंडारी ने कहा, ÷महंगाई बढ़ रही है, जो ब्याज दरों में वृद्धि का समर्थन करती है, जबकि विकास धीमा हो रहा है, जो ब्याज दरों में वृद्धि के खिलाफ तर्क देता है।÷ उन्होंने इसे ÷किसी भी केंद्रीय बैंक के लिए सबसे कठिन स्थिति÷ भी बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि तेल की ऊंची कीमतें और संभावित अल नीनो डेवलपमेंट, महंगाई नियंत्रण, राजकोषीय घाटे और चालू खाते के लिए बाधा बन सकते हैं। केयरएज रेटिंग्स की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि सामान्य से कम मानसून के पूर्वानुमान और हाल ही में खुदरा ईंधन की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के कारण मुद्रास्फीति संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि थोक महंगाई में तीव्र वृद्धि से उपभोक्ता कीमतों पर इसका प्रभाव के तेजी से बढ़ने का खतरा है। महंगाई में मौजूदा उछाल आपूर्ति में अचानक आई कमी के कारण है, न कि मांग में वृद्धि के कारण।

श्री सीमेंट के 'टेक्निकल टॉक्स 2026' का सफल आयोजन

जयपुर ।

श्री सीमेंट लिमिटेड ने इंडियन कंक्रीट इंस्टिट्यूट (आईसीआई) के सहयोग से जयपुर में ÷श्री सीमेंट टेक्निकल टॉक्स 2026÷ का आयोजन किया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के मुख्य अभियंताओं, तकनीकी विशेषज्ञों एवं निर्माण क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों ने भाग लिया। इस मौके पर मुख्य वक्ता प्रदीप गर्ग ने सतत निर्माण एवं कार्बन उत्सर्जन में कमी विषय पर अपने विचार साझा किए, जबकि ए माथुर ने अर्बन ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट विषय पर महत्वपूर्ण प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में डॉ. महेश सिंघल की विशेष उपस्थिति रही। श्री सीमेंट की ओर से अमिताभ सिहाग, गौतम चटर्जी, राजेश सिंघल, विनीत सिंह एवं नितिन शर्मा ने अतिथियों का स्वागत एवं आभार व्यक्त किया।

ओला इलेक्ट्रिक क्यूआईपी के जरिए जुटाएगी पूंजी

नई दिल्ली ।

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, घटती बिक्री और लगातार घाटे के बीच ओला इलेक्ट्रिक ने क्वो लिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के जरिए नई पूंजी जुटाने का फैसला किया है। कंपनी ने इसके लिए प्रति इक्विटी शेयर 37.74 रुपये का फ्लोर प्राइस तय किया है। ओला इलेक्ट्रिक ऐसे समय में यह फंड जुटा रही है, जब वह बिक्री में सुस्ती, बाजार हिस्सेदारी पर बढ़ते दबाव और लगातार घाटे जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। इस कदम का उद्देश्य कंपनी के विस्तार और विनिर्माण योजनाओं को गति देना है। क्यूआईपी के माध्यम से कंपनी म्यूचुअल फंड और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों जैसे बड़े संस्थागत निवेशकों से सीधे पूंजी जुटा सकेगी। इस पूंजी का उपयोग स्थानीय उत्पादन बढ़ाने, सप्लाई चेन पर नियंत्रण हासिल करने और बैटरी सेल व इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट में अपने आक्रामक विस्तार की रणनीति को मजबूत करने में किया जाएगा। कंपनी ने हाल ही में सहायक कंपनियों में 2,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा भी की थी।

तेल कंपनियों को नुकसान, फिर बढ़ सकते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम

कच्चा तेल 100 डॉलर प्रति बैरल के पार, कंपनियों को 12 रुपए प्रति लीटर का घाटा

नई दिल्ली ।

पिछले एक हफ्ते से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भले ही स्थिरता बनी हुई है, लेकिन उपभोक्ताओं को जल्द ही फिर से महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। तेल विपणन कंपनियों को कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में भारी उछाल के कारण प्रति लीटर 12 रुपये तक का नुकसान हो रहा है, जिसकी भरपाई के लिए वे जल्द ही ईंधन की कीमतों में इजाफा कर सकती हैं। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियों को पेट्रोल पर प्रति लीटर 5.5 रुपये और डीजल पर 4.5 रुपये का नुकसान हो रहा है। कुल मिलाकर यह घाटा 12 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया है। मई महीने में भी इन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुल 7.5 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की थी, बावजूद इसके नुकसान की स्थिति बनी हुई है। रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल था, जो अब 100 डॉलर के आंकड़े को पार कर चुका है। इस बढ़ोतरी के कारण भारतीय तेल कंपनियों को रोजाना लगभग 550 करोड़ रुपये का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस स्थिति से निपटने के लिए मूल्य वृद्धि एक संभावित कदम माना जा रहा है। केवल पेट्रोल-डीजल ही नहीं, बल्कि अन्य पेट्रोलियम उत्पादों पर भी कंपनियां घाटा झेल रही हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार,

एलपीजी सिलेंडर पर कंपनियों को प्रति सिलेंडर 650 रुपये का नुकसान हो रहा है, वहीं एविएशन टरबाइन फ्यूल पर 30 रुपये प्रति लीटर का घाटा है। गौरतलब है कि युद्ध शुरू होने के बाद 76 दिनों तक ईंधन की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी, जिसके बाद 4 बार कीमतें बढ़ाई गईं। वाणिज्यिक गैस सिलेंडर के दाम भी मार्च से अब तक 47 फीसदी से अधिक बढ़ चुके हैं, जिसमें हाल ही में 1 जून को 40 रुपये की वृद्धि भी शामिल है।

केंद्रीय कर्मचारियों को 63 फीसदी डीए जुलाई से, 3 फीसदी होगी बढ़ोतरी

सितंबर-अक्टूबर में घोषणा की उम्मीद

नई दिल्ली ।

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। अनुमान है कि केंद्र सरकार उनके महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है। इस वृद्धि के बाद कर्मचारियों का डीए 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा, जो जुलाई 2026 से प्रभावी माना जाएगा। इस फैसले से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जिसकी घोषणा सितंबर या अक्टूबर माह में की जा सकती है। लेबर ब्यूरो की ओर से जारी नवीनतम महंगाई के आंकड़ों से संकेत मिल रहे हैं कि महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ सकता है। अप्रैल 2026 के लिए जारी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स डेटा 149.9 पर पहुंच गया है, जिसके आधार पर जून तक गणना 63 फीसदी से ऊपर रहने का अनुमान है। चूंकि डीए को आमतौर पर पूरे अंक में लागू किया जाता है, इसलिए जुलाई से 63 फीसदी डीए मिलने की पूरी संभावना है। इस बढ़ोतरी की घोषणा सितंबर या अक्टूबर में होने की उम्मीद है। यदि घोषणा सितंबर में होती है, तो कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर के तीन महीनों का एरियर मिलेगा। वहीं अक्टूबर में ऐलान होने पर चार महीने (जुलाई से अक्टूबर) का एरियर देय होगा। उदाहरण के लिए, 18,000 रुपये का न्यूनतम मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी की मासिक डीए में 540 रुपये की

वृद्धि होगी, जिससे सितंबर में 1500 रुपये से अधिक और अक्टूबर में 2000 रुपये से अधिक का एरियर मिलेगा।

ट्रांसरेल लाइटिंग को 575 करोड़ के नए ठेके, मजबूत हुई ऑर्डर बुक

नई दिल्ली ।

इंजीनियरिंग, खरीद एवं निर्माण (ईपीसी) कंपनी ट्रांसरेल लाइटिंग ने हाल ही में 575 करोड़ रुपये के नए ठेके हासिल किए हैं। ये ठेके मुख्य रूप से पारेषण एवं वितरण (टीएंडडी), सिविल निर्माण और पोल आपूर्ति क्षेत्रों से संबंधित हैं, जो कंपनी के बढ़ते कारोबार को दर्शाते हैं। कंपनी के एक अधिकारी के अनुसार इन नए ठेकों में एक बड़े ग्राहक के लिए 500 केवी एचवीडीसी लाइन का निर्माण, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उत्पादों की आपूर्ति और विशेष सिविल निर्माण कार्य शामिल हैं। यह ट्रांसरेल लाइटिंग की विविध क्षमताओं का प्रमाण है। 31 मार्च तक कंपनी की कुल ऑर्डर बुक 16,361 करोड़ रुपये पहुंच गई है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक है। यह कंपनी की मजबूत स्थिति और भविष्य की विकास संभावनाओं को उजागर करती है। मुंबई स्थित यह ईपीसी कंपनी मुख्य रूप से टीएंडडी क्षेत्र में सक्रिय है और वर्तमान में 63 देशों में अपनी सेवाएं दे रही है।

निफ्टी का लक्ष्य 27,220 पर बरकरार, 15 पसंदीदा शेयरों की सूची जारी

नई दिल्ली ।

भारतीय शेयर बाजार इस समय पश्चिम एशिया में तनाव, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और विदेशी बिकवाली जैसे कई दबावों का सामना कर रहा है। इसके बावजूद ब्रोकरेज हाउस एक्सिस सिक्योरिटीज ने भारत की आर्थिक बुनियाद पर अपना भरोसा कायम रखा है।

ब्रोकरेज ने दिसंबर 2026 के लिए निफ्टी का लक्ष्य 27,220 पर बरकरार रखा है और लंबी अवधि के निवेशकों के लिए 15 पसंदीदा शेयरों की सूची जारी की है।

मई 2026 के दौरान बाजार में उतार-चढ़ाव दिखा; जहां निफ्टी 50 बैंकिंग, आईटी और तेल शेयरों में कमजोरी से दबाव में रहा, वहीं मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों ने रिकॉर्ड ऊंचाई छूकर बेहतर प्रदर्शन किया। निवेशकों का रुझान इंडस्ट्रियल्स, कैपिटल गुड्स, डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टरों की ओर बढ़ा है। मार्च तिमाही के नतीजे सकारात्मक रहे, निफ्टी 500 कंपनियों की आय में 9 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई।

प्रबंधन` वित्त वर्ष 27 की दूसरी छमाही में मांग सुधार को लेकर सतर्क रूप से आशावादी है, जिसे सरकारी खर्च और निजी निवेश से बल मिलेगा। हालांकि, एक्सिस सिक्योरिटीज ने बढ़ती महंगाई को बाजार के लिए सबसे बड़ा जोखिम बताया है। पश्चिम एशिया तनाव से कच्चे तेल की ऊंची कीमतें भारत की आयात-निर्भर अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डाल रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार डीजल की कीमतों में वृद्धि परिवहन, कृषि और लॉजिस्टिक्स सहित कई क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है, जिससे महं

कोका-कोला भारतीय बॉटलिंग इकाई का आईपीओ लाएगी, 2027 में सूचीबद्धता की तैयारी

एचसीसीएच में हिस्सेदारी बेचने पर भी विचार, वैश्विक एसेट-लाइट रणनीति का हिस्सा

नई दिल्ली ।

वैश्विक पेय पदार्थ कंपनी कोका-कोला 2027 तक अपनी भारतीय बॉटलिंग इकाई की मूल कंपनी हिंदुस्तान कोका-कोला होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (एचसीसीएच) को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने पर विचार कर रही है।

इसके साथ ही कंपनी एचसीसीएच में अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा बेचने पर भी मंथन कर रही है।

यह कदम कोका-कोला की वैश्विक एसेट-लाइट रणनीति का हिस्सा है। कंपनी ने बताया कि वह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने की प्रारंभिक तैयारियां कर रही है, जो बाजार की स्थितियों और नियामकीय मंजूरियों पर निर्भर करेगा।

एचसीसीएच, भारत में कोका-कोला के सबसे बड़े बॉटलिंग व्यवसाय, हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेज (एचसीसीबी) की मूल कंपनी है। भारत कोका-कोला के लिए दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा बाजार है। यह संभावित सूचीकरण कंपनी की वैश्विक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वह अपने बॉटलिंग कारोबार में हिस्सेदारी घटा रही है। लगभग एक साल पहले ही कोका-कोला ने एचसीसीएच में अपनी 40त्न हिस्सेदारी जुबिलेंट भारतीय ग्रुप को बेची थी।

एचसीसीबी की स्थापना 1997 में हुई थी और यह देशभर में 14 बॉटलिंग संयंत्र संचालित करती है। कंपनी भारत में कोका-कोला, थम्स अप, स्प्राइट, माजा, किनले और फैंटा जैसे कई लोकप्रिय उत्पाद बनाती एवं बेचती है।

एक परिवार, एक गैस कनेक्शन का नियम लागू; अतिरिक्त कनेक्शन पर होगी कार्रवाई

पीएनजी यूजर्स को 30 दिन में एलपीजी स्टेटस करना होगा स्पष्ट

नई दिल्ली ।

देशभर में एलपीजी और पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) उपभोक्ताओं के लिए गैस कनेक्शन नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब अगर किसी उपभोक्ता ने अपने घर में पीएनजी कनेक्शन लगवाया है, तो उसे 30 दिनों के भीतर अपने एलपीजी कनेक्शन की स्थिति स्पष्ट करनी होगी, अन्यथा अतिरिक्त कनेक्शनों पर कार्रवाई की जा सकती है। यह नया नियम पारदर्शिता लाने और गैस वितरण व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि एक ही रसोई का उपयोग करने वाले परिवार के लिए केवल एक ही घरेलू गैस कनेक्शन (एलपीजी या पीएनजी) पर्याप्त माना जाएगा। जांच के दौरान एक ही परिवार के नाम पर एक से अधिक घरेलू एलपीजी कनेक्शन पाए जाने पर अतिरिक्त कनेक्शन को नियमों के तहत हटाया जा सकता है, जिससे गैस आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। संबंधित एजेंसियां ऐसे मामलों की जांच करेंगी और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त कनेक्शन को बंद करेंगी। हालांकि, सरकार ने उपभोक्ताओं को कुछ राहतें भी दी हैं। जो उपभोक्ता स्वेच्छा से अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करेंगे, उन्हें मौजूदा कनेक्शन को डबल बॉटल कनेक्शन (डीबीसी) में बदलने का विकल्प मिलेगा। साथ ही एलपीजी कनेक्शन बंद करने पर ट्रांसफर वाउचर दिया जाएगा, जिससे भविष्य में पीएनजी रहित क्षेत्रों में जाने पर एलपीजी कनेक्शन दोबारा सक्रिय करवाना आसान होगा। यह सुविधा खासकर नौकरीपेशा, छात्रों, किराएदारों और प्रवासी परिवारों के लिए फायदेमंद होगी, जिससे स्थान बदलने की स्थिति में औपचारिकताएं सरल होंगी और गैस वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी।

खनन कंपनियों से 1000 करोड़ से अधिक राजस्व वसूलेगी झारखंड सरकार

धनबाद में खनन से सरकारी जमीन के उपयोग पर बड़ा खुलासा

धनबाद ।

झारखंड विधानसभा की विशेष समिति ने धनबाद परिसदन में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल), ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) समेत अन्य खनन कंपनियों द्वारा रैयतों, सरकारी व वन भूमि पर अवैध खनन और ओवरबर्डन डंपिंग की समस्या की समीक्षा की। इस समीक्षा के बाद समिति ने खुलासा किया कि इन कंपनियों ने बिना अनुमति सरकारी भूमि का उपयोग किया है, जिससे राज्य सरकार को 1000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त होगा। समिति के सभापति सह टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने बताया कि विभिन्न कोल कंपनियों ने रैयतों और सरकारी जमीन का उपयोग किया है। बीसीसीएल ने सरकारी जमीन के उपयोग के लिए पहले ही 220 करोड़ रुपए राजस्व जमा करा दिए हैं। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) और ईसीएल ने भी सरकारी जमीन के इस्तेमाल की बात स्वीकार करते हुए राजस्व भुगतान पर सहमति दी है, जिससे राज्य सरकार को कुल 1000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व मिलेगा। महतो ने जोर दिया कि समिति के आकलन से राज्य सरकार के साथ-साथ रैयतों को भी आर्थिक लाभ होगा। उन्होंने बताया कि नौ महीने पहले सिंदरी विधायक द्वारा ओवरबर्डन डंपिंग का मामला संज्ञान में लाए जाने के बाद ही इस समिति का गठन किया गया था। समिति यह सुनिश्चित कर रही है कि जिन रैयतों की जमीन खनन के लिए उपयोग की गई है, उन्हें पूरा मुआवजा मिले।

इसके लिए जिला प्रशासन और बीसीसीएल को रैयतों की समस्या का सरल तरीके से निपटारा करने का निर्देश दिया गया है। बैठक में क्षेत्र की अन्य समस्याओं और विकास कार्यों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

दिल्ली के मुकुंदपुर में सिलेंडर फटने से ढहा मकान

-मलबे से सुरक्षित निकाले गए छह लोग

नई दिल्ली (एजेंसी)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भलस्वा डेरी के पास मुकुंदपुर इलाके से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। यहाँ के इशु विहार की गली नंबर 1 में सुबह अचानक एक एलपीजी सिलेंडर फट गया, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना भीषण था कि लगभग 250 वर्ग गज में बना एक मंजिला मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इस घटना से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की पाँच गाड़ियाँ तुरंत मौके पर पहुँचीं। आपातकालीन और बचाव टीमों ने स्थानीय लोगों की मदद से फौरन सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। राहत की बात यह रही कि अब तक मलबे के नीचे से दो महिलाओं सहित कुल छह लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इनमें से दो लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी बीएसए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि इस मकान में कुछ मजदूर अपने परिवार के साथ रहते थे। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और मलबे को हटाया जा रहा है।

बांद्रा में बिना अनुमति उड़ाए सैकड़ों ड्रोन, पुलिस ने मैनेजर को हिरासत में लिया

-ड्रोन समेत अन्य उपकरण जब्त, एक ड्रोन की कीमत करीब 80 हजार रुपए

मुंबई (एजेंसी)। मुंबई में बांद्रा पश्चिम में बड़े पैमाने पर बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि मुंबई पुलिस आयुक्त द्वारा जारी निषेधाज्ञा और सुरक्षा संबंधी नियमों की अनदेखी करते हुए मैदान में करीब 200 से 250 ड्रोन उड़ाकर वीडियो शूटिंग की जा रही थी सूचना मिलने पर बांद्रा पुलिस की टीम ने मौके पर छापेमारी कर एक निजी कंपनी के मैनेजर को हिरासत में लिया और बड़ी संख्या में ड्रोन समेत अन्य उपकरण जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक 28 मई की रात बांद्रा पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन स्टाफ को सूचना मिली थी कि बांद्रा पश्चिम स्थित विंग्स स्पोर्ट क्लब ग्राउंड में बड़ी संख्या में ड्रोन उड़ाकर वीडियो शूटिंग की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो आसमान में सैकड़ों ड्रोन उड़ते हुए दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर ड्रोन संचालन रुकवाया और मौके पर मौजूद व्यक्ति को हिरासत में लिया जिसकी पहचान गोपाल नारायण सिंह (45) के रूप में हुई, जो दक्षिण दिल्ली के संगम विहार का रहने वाला है। उसने पुलिस को बताया कि वह बोल्डसन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में मैनेजर के पद पर कार्यरत है और कंपनी के विज्ञापन के लिए ड्रोन आधारित शूटिंग की जा रही थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस पूछताछ में गोपाल से ड्रोन संचालन की अनुमति, आवश्यक लाइसेंस और मुंबई पुलिस आयुक्त कार्यालय से प्राप्त मंजूरी से जुड़े दस्तावेज मांगे गए। हालांकि वह कोई वैध अनुमति पत्र या अधिकृत दस्तावेज पेश नहीं कर सका। जांच में कंपनी के एक अन्य पदाधिकारी सुनील गुप्ता का नाम भी सामने आया है, जो कई विभागों से अनुमति लेने की प्रक्रिया देखता था। आरोप है कि मंजूरी प्राप्त किए बिना ही ड्रोन शो और शूटिंग शुरू कर दी गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने बड़ी संख्या में हाई-टेक ड्रोन, कंट्रोल सिस्टम, ऑपरेटिंग किट और एक लैपटॉप जब्त किया है।

आरे में अवैध दरगाह पर चला बुलडोजर, 70,000 वर्ग फुट सरकारी जमीन मुक्त

मुंबई (एजेंसी)। मुंबई के गोरेगांव (पूर्व) स्थित आरे मिल्क कॉलोनी (यूनिट 32) में स्थित हजरत सैयद बरकत अली शाह बाबा दरगाह पर जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। करीब 70,000 वर्ग फुट सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी दरगाह को ध्वस्त करने के लिए तीन बुलडोजर चलाए गए। यह कार्रवाई सुबह 11 बजे के बाद शुरू हुई और इसके मद्देनजर पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। आरोप है कि यह दरगाह दशकों से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई थी, जबकि लोग इस दरगाह को पुरानी और वैध बताने का दावा कर रहे थे। आरे कॉलोनी एक सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, और ध्वस्तीकरण के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। सुरक्षा एजेंसियों ने कथित तौर पर संभावित सुरक्षा जोखिमों के बारे में जिला प्रशासन को पहले ही पत्र लिखकर अवगत कराया था, जिसके बाद प्रशासनिक स्तर पर इस मामले की कड़ी निगरानी की जा रही थी। इस मुद्दे को बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने पिछले साल अप्रैल में प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने आरे कॉलोनी में कथित अवैध दरगाह और अतिक्रमण पर कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद यह मामला काफी सुर्खियों में रहा। बीजेपी नेता सोमैया ने कार्रवाई से कुछ ही दिन पहले इस दरगाह का दौरा भी किया था।

सीएम योगी ने फाजिलनगर का नाम बदलकर पावागढ़ किया

कुशीनगर (एजेंसी)। उत्तरप्रदेश के कुशीनगर जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एक बड़ा ऐलान कर फाजिलनगर का नाम बदलकर पावागढ़ रखने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी ने कुशीनगर की जनता को संबोधित कर ऐतिहासिक निर्णय की जानकारी दी, जिसका लोगों द्वारा लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। सीएम योगी ने कहा कि अब यह क्षेत्र फाजिलनगर नहीं बल्कि पावागढ़ के रूप में मान्यता प्राप्त करेगा और इसे भगवान महावीर के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया, क्यों हम फाजिल कहे! और इस बदलाव को वर्तमान पीढ़ी का बड़ा सौभाग्य बताया। मुख्यमंत्री योगी ने संकेत दिया कि लोगों की मांग पर विधायक और सांसद मिलकर काम कर रहे थे, और अब नामकरण का प्रस्ताव भी आगे बढ़ा दिया गया है। अपने भाषण में मुख्यमंत्री योगी ने अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का जिक्र कर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि करीब 498 वर्ष पहले एक विदेशी आक्रांता ने राम मंदिर को तोड़ने का कुत्सित प्रयास किया था, और कई पीढ़ियों तक मंदिर निर्माण में बाधाएं आती रहीं। सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि डबल इंजन की भाजपा सरकार के प्रयासों से ही राम मंदिर निर्माण का सपना साकार हो सका, जबकि कांग्रेस और सपा जैसे दल इसके मार्ग में रोड़े अटका रहे थे और घोषित रामद्रोही थे। मुख्यमंत्री योगी ने मतदाताओं की शक्ति पर जोर देकर कहा कि फाजिलनगर, पडरौना, खड्डा या हाटा जैसे क्षेत्रों में दिया गया एक-एक वोट लखनऊ और दिल्ली में अपनी ताकत दिखाता है। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि इसी वोट की शक्ति से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण संभव हुआ, जम्मू-कश्मीर से धारा 370 समाप्त हुई, और पाकिस्तान को थर्रा देने वाली मिसाइलों का निर्माण लखनऊ में हो रहा है।

महाराष्ट्र और बंगाल में महिलाओं की योजना का लाखों अपात्र लोग ले रहे लाभ

राज्य सरकारें जांच के जरिए वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करने में जुटी

नई दिल्ली (एजेंसी)। महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से शुरू की गई सरकारी योजनाएं अब पात्रता और पारदर्शिता के सवालों के घेरे में हैं। महाराष्ट्र में लाड़की बहिन योजना से करीब 80 लाख लाभार्थियों के नाम हटाए जाने के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक बहस छिड़ गई है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी लक्ष्मी भंडार योजना के तहत लाखों अपात्र लोगों के लाभ लेने का दावा किया गया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के लिए लाई गई इन योजनाओं का लाभ दोनों ही राज्यों में पुरुष भी ले रहे थे, जिसके बाद ये कदम उठाए गए हैं। दोनों राज्यों में सरकारें अब ई-केवाईसी, दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की नई जांच के जरिए वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करने में जुटी हैं, जिससे इन महत्वाकांक्षी कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। बता दें महाराष्ट्र में प्रदेश सरकार की लाड़की बहिन योजना को लेकर एक अहम जानकारी सामने आई है। राज्य सरकार ने अनिवार्य ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी न करने वाले करीब 80 लाख लाभार्थियों के खाते बंद कर दिए हैं। ये कार्रवाई योजना को लेकर आ रही शिकायत के बाद की गई है। इस योजना का फायदा अपात्र भी उठा रहे थे।

जांच में सामने आया था कि कुछ पुरुष और सरकारी कर्मचारी भी गलत तरीके से 1500 रुपए की मासिक राशि ले रहे थे। इस धांधली को रोकने के लिए वेरिफिकेशन और ई-केवाईसी का अभियान शुरू किया गया था। वेरिफिकेशन में एक तकनीकी पेच भी फंसा। रिपोर्ट के मुताबिक मराठी भाषा में पूछे गए एक सवाल के गलत जवाब की वजह से करीब 24 लाख महिलाओं को सरकारी कर्मचारी मान लिया गया था। हालांकि, बाद में हुई जांच में इनमें से 20 लाख महिलाएं पूरी तरह पात्र पाई गईं थीं।

प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में लाभार्थियों की संख्या कम होने को लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा केवल ई-केवाईसी लंबित रहने से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई अन्य कारण भी हैं। तटकरे ने बताया कि सरकार ने ई-केवाईसी के लिए शुरुआती समयसीमा तय की थी, जिसे बाद में कई बार बढ़ाया गया। कुल मिलाकर लाभार्थियों को करीब 8 से 10 महीने का समय दिया गया। उन्होंने कहा कि यह सत्यापन प्रक्रिया राज्य की सभी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनाओं में अपनाई जाती है, केवल लाड़की बहिन योजना तक सीमित नहीं है।

मंत्री तटकरे के मुताबिक पिछले 10 महीनों में किए गए डेटा सत्यापन में 11 से 12 लाख ऐसे लाभार्थी पाए गए, जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है। इसके अलावा करीब 4.75 से 5 लाख महिलाएं 65 साल की आयु सीमा पार कर चुकी हैं, जिसके कारण वे योजना के दायरे से बाहर हो गईं। तटकरे ने बताया कि करीब 14 हजार सरकारी कर्मचारी भी लाभार्थियों की सूची में शामिल पाए गए थे, इसके अलावा कुछ ऐसे किसान भी चिन्हित किए गए हैं, जो अन्य योजनाओं का लाभ भी ले रहे थे। करीब 3.25 लाख लाभार्थियों के नाम पर पंजीकृत वाहन भी पाए गए हैं।

वहीं, बीते हफ्ते पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने प्रदेश की लक्ष्मी भंडार को लेकर कहा था कि इस योजना का लाभ ले रहे कीरब 30 लाख लाभार्थी अपात्र हैं। इनमें से कई गैर-भारतीय हैं या उनके नाम वोटर लिस्ट से स्थायी रूप से हटाए जा चुके हैं। सीएम अधिकारी ने नई 'अन्नपूर्णा भंडार' योजना के लिए आवेदन फॉर्म जारी किया था। उन्होंने कहा कि पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना के तहत अधिकारियों द्वारा आवेदन पत्रों का सत्यापन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत आवेदन किया है या एसआईआर से जुड़े ट्रिब्यूनल में वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए अपील की है, वे इस योजना के पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को बड़ी संख्या में शिकायतें मिली थीं कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हट चुके हैं और जिन्होंने ट्रिब्यूनल या सीएए के तहत आवेदन नहीं किया, वे भी योजना का लाभ ले रहे थे। सरकार 1 जून से 90 दिनों तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से नामांकन प्रक्रिया शुरु कर दी है। पंचायत क्षेत्रों में अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर फॉर्म भरवाने का अभियान भी शुरू किया जाएगा। सीएम अधिकारी ने दावा किया कि सत्यापन की कमी के कारण योजना में पुरुष लाभार्थियों के नाम भी शामिल हो गए थे। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं 2 जून तक सफलतापूर्वक नामांकन करा लेंगी, उन्हें अगले कैबिनेट बैठक के बाद डीबीटी के जरिए राशि भेजी जाएगी।

बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट की जज बनेंगी वी. मोहना

-हिजाब बैन से लेकर सैन्य महिला अधिकारियों के मामलों तक की पैरवी

-शीर्ष अदालत में महिला जजों की संख्या बढ़कर दो होगी

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश की वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश नियुक्त किए जाने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार द्वारा कॉलेजियम की सिफारिश स्वीकार किए जाने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने से उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। खास बात यह है कि वी. मोहना बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली दूसरी महिला होंगी। इससे पहले वर्ष 2018 में जस्टिस इंदु मल्होत्रा को वकालत से सीधे शीर्ष अदालत में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।

59 वर्षीय वी. मोहना का न्यायिक और विधिक क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है। उन्होंने वर्ष 1988 में कोयंबटूर लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई पूरी की और तब से लगातार वकालत कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2015 में उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता (सीनियर एडवोकेट) का दर्जा प्रदान किया था। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण और चर्चित मामलों में पक्ष रखा। इनमें सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों की सेवा शर्तों से जुड़े मामले, वरिष्ठ नागरिकों के संपत्ति अधिकारों से संबंधित विवाद तथा कर्नाटक में हिजाब प्रतिबंध से जुड़े प्रकरण प्रमुख रहे हैं।

वी. मोहना की नियुक्ति के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर दो हो जाएगी। पिछले कई महीनों से जस्टिस बी. वी. नागरत्ना शीर्ष अदालत की एकमात्र महिला जज थीं। जस्टिस नागरत्ना अगस्त 2021 से सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत हैं और वर्ष 2027 में देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की संभावना रखती हैं।

सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में वी. मोहना 12वीं महिला न्यायाधीश होंगी। इससे पहले जस्टिस एम. फातिमा बीवी 1989 में शीर्ष अदालत की पहली महिला जज बनी थीं। वहीं, जस्टिस इंदु मल्होत्रा बार से सीधे नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश थीं।

वंदे मातरम के पांच अंतरे हर कार्यक्रम में अनिवार्य करना अनावश्यक और बोझिल

-शशि थरूर ने वंदे मातरम के सभी पांच अंतरे गाए जाने की अनिवार्यता पर उठाए सवाल

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने आधिकारिक कार्यक्रमों के शुरुआत और अंत में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सभी पांच अंतरे गाए जाने की अनिवार्यता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। केरल में राष्ट्रगीत के गायन को लेकर छिड़े एक नए विवाद के बीच, थरूर ने इस प्रथा को श्रोताओं के लिए अनावश्यक और बोझिल बताया है। केरल में राष्ट्रगीत के गायन को लेकर जारी विवाद के बीच थरूर ने कहा कि वंदे मातरम का सभी सम्मान करते हैं, लेकिन हर समारोह में इसके सभी अंतरे बजाने को अनिवार्य करना तर्कसंगत नहीं है।

उन्होंने कहा कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत है और जब इसे गाया जाता है तो हम सम्मानपूर्वक खड़े हो जाते हैं। इसका पहला अंतरा या शुरुआती दो अंतरे, ज्यादातर लोगों को मुंह जुबानी याद होते हैं। थरूर ने कहा कि परंपरागत रूप से यह गीत किसी कार्यक्रम की शुरुआत में एक बार गाया जाता है, जबकि राष्ट्रगान अलग से, अक्सर अंत में बजाया जाता है। उन्होंने कहा कि अब वे चाहते हैं कि हर कार्यक्रम की शुरुआत में और अंत में पांचों अंतरे गाए जाएं। मुझे लगता है कि यह एक अनावश्यक थोपा हुआ नियम है। थारूर ने जोर दिया कि उन्हें राष्ट्रगीत से कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सभी वंदे मातरम का सम्मान करते हैं। मैं खुशी-खुशी इसे आपके लिए गा सकता हूं।

बता दें वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 के दशक में की थी। बाद में इसे उनके प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास आनंदमठ (1882) में शामिल किया गया। यह मूल रूप से संस्कृत और बंगाली भाषा के मिश्रण में लिखा गया है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह गीत देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक बनकर उभरा। साल 1896 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में रवींद्रनाथ टैगोर ने पहली बार इसे राजनीतिक मंच पर गाया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जन गण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की थी कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर ही सम्मान दिया जाएगा।

टीएमसी के 50 विधायक बदल सकते हैं पाला

-चुनाव चिन्ह भी पड़ सकता है खतरे में

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में सत्ता से बेदखल हुई टीएमसी अब अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। पार्टी के 50 विधायक पाला बदलने के लिए सौदेबाजी करते सुनाई दे रहे हैं। पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी द्वारा सोमवार को दो विधायकों को निष्कासित किए जाने के बाद से राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं कि टीएमसी के करीब 50 विधायक पार्टी से अलग हो सकते हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब कई पार्षद लगातार अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं और पार्टी के बड़े नेता आधिकारिक कार्यक्रमों से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। दो विधायकों के निष्कासन के बाद अब विधानसभा में टीएमसी के सदस्यों की संख्या घटकर 78 रह गई है। राजनीतिक हल्कों में इस बात की पुरजोर चर्चा है कि निष्कासित विधायक रीताब्रत बनर्जी और संदीपन साहा के नेतृत्व में एक नई तृणमूल का गठन किया जा सकता है, हालांकि अभी तक किसी भी नेता ने इस पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है।

दूसरी तरफ, राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी इन दोनों विधायकों का विशेष रूप से जिक्र किया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, हावड़ा की उलुबेरिया पूर्व सीट से विधायक रीताब्रत बनर्जी और मध्य कोलकाता के एंटाली से विधायक संदीपन साहा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों के आधार पर ही विधानसभा सचिवालय ने विधायक दल के जाली हस्ताक्षर का मामला पुलिस में दर्ज कराया था। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि यह जांच किसी अन्य दल द्वारा शुरू नहीं की गई थी, बल्कि खुद टीएमसी के इन दो विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के सामने शिकायत दर्ज कराई थी। विधायकों का आरोप था कि विपक्ष के नेता के चयन से संबंधित बैठक में ऐसा कोई प्रस्ताव पारित ही नहीं हुआ था और 70 विधायकों के हस्ताक्षर वाला समर्थन पत्र पूरी तरह फर्जी और मनगढ़ंत है। इस पूरे विवाद ने बंगाल की सियासत को बेहद संवेदनशील मोड़ पर ला खड़ा किया है।

तो महाराष्ट्र जैसी बन जाएगी स्थिति

यदि टीएमसी के 50 विधायक अलग होकर एक नया गुट बनाते हैं, तो बंगाल में भी महाराष्ट्र जैसा राजनीतिक परिदृश्य देखने को मिल सकता है। जिस तरह महाराष्ट्र में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) में बड़ी बगावत के बाद मूल कप्तानों को अपनी ही पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न गंवाना पड़ा था, वैसी ही स्थिति यहाँ भी बन सकती है। टीएमसी नेतृत्व ने जिन दो विधायकों पर कार्रवाई की है, उन्हें भेजे गए पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने के बावजूद वे आधिकारिक बैठकों से लगातार नदारद रहे और खुद को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल किया। पार्टी उपाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित इस पत्र में आरोप लगाया गया है कि इन विधायकों के बयान और कदम संगठन के हितों के पूरी तरह खिलाफ थे, जिसके कारण उन्हें प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया गया।

भजनलाल ने की पीएम मोदी से मुलाकात, सरकार के कामकाज का दिया फीडबैक

नई दिल्ली (एजेंसी)। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाक़ात की। प्रदेश में होने जा रहे राज्यसभा चुनाव के मद्देनज़र यह मुलाक़ात अहम मानी जा रही है। सीएम भजनलाल ने सरकार के कामकाज को लेकर भी पीएम मोदी को फीडबैक दिया। जानकारी के मुताबिक सोमवार को करीब एक घंटे से ज्यादा दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई थी। वहीं इस मुलाक़ात को प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाली राजनीतिक नियुक्तियों से भी जोड़ा जा रहा है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर से लेकर दिल्ली तक चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन असल वजह क्या है? ये कोई पुख्ता नहीं कर रहा। बता दें पिछले तीन महीने में सीएम की पीएम मोदी से यह तीसरी मुलाकात है। इससे पहले फ़रवरी और मार्च महीने में भी पीएम से मुलाक़ात हुई थी। बताया जा रहा है कि सीएम भजनलाल ने प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाओं सहित आगामी योजना की जानकारी पीएम मोदी को दी, साथ ही केंद्र के साथ मिलकर चल रही योजनाओं पर भी चर्चा की।

अन्नामलाई ने नितिन नवीन से की मुलाकात, अटकलों का दौर जारी

-राज्यसभा और संगठन में नई भूमिका को लेकर चर्चाएं गर्म

नई दिल्ली (एजेंसी)। तमिलनाडु भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के राजनीतिक भविष्य को लेकर चल रही अटकलों के बीच उनकी दिल्ली यात्रा ने नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। भाजपा छोड़कर नई पार्टी बनाने की अफवाहों के बीच अन्नामलाई ने पार्टी मुख्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और संगठन महामंत्री बीएल संन्तोष से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार बैठक में उनके संभावित नए दायित्वों और संगठन में भविष्य की भूमिका को लेकर चर्चा हुई।

जानकारी के मुताबिक भाजपा नेतृत्व ने अन्नामलाई को भरोसा दिलाया कि पार्टी उनकी क्षमता और संगठनात्मक योगदान के अनुरूप उन्हें आगे भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देती रहेगी। बताया जा रहा है कि दिल्ली प्रवास के दौरान वह पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। अन्नामलाई की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब उनके भाजपा छोड़ने, नई राजनीतिक पार्टी बनाने अथवा राज्यसभा भेजे जाने जैसी संभावनाओं को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। हालांकि उन्होंने इन अटकलों पर खुलकर कुछ भी कहने से इनकार किया है। दिल्ली आने से पहले पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने केवल इतना कहा था, 'कृपया इंतजार कीजिए, दो दिन बाद हम बैठकर बात करेंगे।' उनके इस बयान ने राजनीतिक हलकों में उत्सुकता और बढ़ा दी है।

बहुत कम समय में पार्टी का प्रमुख चेहरा बने

पूर्व आईपीएस अधिकारी अन्नामलाई वर्ष 2020 में भाजपा में शामिल हुए थे। कम समय में ही उन्होंने तमिलनाडु में पार्टी के प्रमुख चेहरों में अपनी पहचान बनाई। वर्ष 2021 से 2025 तक प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कई राज्यव्यापी अभियानों का नेतृत्व किया और युवाओं तथा सोशल मीडिया पर मजबूत जनाधार तैयार किया। हाल ही में संपन्न तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद उनके भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हुईं, क्योंकि पार्टी का प्रमुख चेहरा होने के बावजूद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। इसके अलावा कक्षा नौ के विद्यार्थियों के लिए त्रिभाषा नीति को लेकर केंद्र सरकार के निर्णय पर उनकी आलोचनात्मक टिप्पणी ने भी राजनीतिक बहस को हवा दी और पार्टी नेतृत्व के साथ उनके संबंधों को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए। फिलहाल भाजपा नेतृत्व और अन्नामलाई की बैठकों पर सभी की नजरें टिकी हैं। आने वाले दिनों में उनकी भूमिका को लेकर कोई महत्वपूर्ण घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है।

नीट मामला और प्रशासनिक चूकों को लेकर युवा कांग्रेस का देशव्यापी आंदोलन

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से तत्काल हटाए जाने की मांग

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक और प्रशासनिक चूकों को लेकर राजनीति तेज हो गई है। भारतीय युवा कांग्रेस ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ अपने देशव्यापी आंदोलन को और उग्र करने का ऐलान किया है। युवा कांग्रेस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से तत्काल हटाए जाने की अपनी मांग को दोहराया है। कांग्रेस की युवा इकाई ने साफ कहा है कि परीक्षाओं से जुड़े बार-बार के विवादों ने देश की शिक्षा व्यवस्था और चयन प्रक्रियाओं में छात्रों के भरोसे को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है।

कांग्रेस की युवा इकाई ने कहा कि वह कई राज्यों में विरोध प्रदर्शनों का नया चरण शुरू करेगी जिसके तहत मशाल जुलूस निकाले जाएंगे, छात्रों से संपर्क करने के कार्यक्रम चलाए जाएंगे और प्रदर्शन एवं घेराव किया जाएगा। संगठन ने कहा कि परीक्षाओं संबंधी बार-बार पैदा होने वाले विवादों से शिक्षा व्यवस्था में छात्रों का भरोसा कमजोर हुआ है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब इस अभियान का नेतृत्व करने के लिए कई राज्यों का दौरा करेंगे। यह अभियान महाराष्ट्र, तेलंगाना, असम, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में चलाया जाएगा।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि विभिन्न भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने, परीक्षा संबंधी अनियमितताएं होने और प्रशासनिक चूक के कारण छात्रों को बार-बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संगठन ने परीक्षाएं कराने से जुड़ी संदिग्ध संस्थाओं को ठेके दिए जाने संबंधी खबरों पर भी चिंता जताई। भारतीय युवा कांग्रेस के प्रभारी मनीष शर्मा ने कहा कि इस देश के छात्र रोजगार, न्याय और जवाबदेही के हकदार हैं। इसके बजाय उन्हें प्रश्नपत्र लीक, अनिश्चितता और चरमराई हुई परीक्षा व्यवस्था मिली है। उन्होंने कहा कि संगठन अपना विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रखेगा, जब तक जवाबदेही तय नहीं होती और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को हटाया नहीं जाता।

चिब ने सरकार पर छात्रों की चिंताओं को दूर करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि परीक्षाओं के पेपर लीक होने एवं अनियमितताओं के कारण युवा अभ्यर्थियों के भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि अब हम इस आंदोलन को पूरे देश में तेज कर रहे हैं। हम तब तक नहीं रुकेंगे, जब तक पीएम मोदी धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने के लिए मजबूर नहीं हो जाते।

सिंधु जलसंधि पर खेल-1 अगस्त से भारत कर रहा नदी जोड़ो प्रोजेक्ट्स का काम शुरु

-चिनाब नदी के पानी को ब्यास नदी बेसिन में मोड़ा जाएगा, 2029 तक का लक्ष्य

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार इस साल 1 अगस्त से अपने सबसे महत्वाकांक्षी नदी जोड़ो प्रोजेक्ट्स में से एक पर काम शुरू करने जा रही है। करीब 2,300 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट को 31 जुलाई 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके तहत चिनाब नदी के अतिरिक्त पानी को ब्यास नदी बेसिन में मोड़ा जाएगा।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एनएचपीसी के एक दस्तावेज के मुताबिक 'लिंक-3 प्रोजेक्ट' हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले की लाहौल घाटी में चिनाब नदी पर प्रस्तावित है। इस योजना के तहत चिनाब नदी पर 19 मीटर ऊंचा बैराज बनाया जाएगा। इसके साथ एक इंटेक स्ट्रक्चर और करीब 8.7 किलोमीटर लंबी जल परिवहन सुरंग का निर्माण किया जाएगा। परियोजना के दूसरे चरण में जलविद्युत उत्पादन की भी संभावना रखी गई है। दस्तावेज में बताया गया है कि प्रस्तावित बैराज के आसपास का इलाका बेहद दुर्गम और पहाड़ी है। यहां चिनाब नदी एक चौड़ी यू-आकार की घाटी से होकर बहती है। क्षेत्र की ऊंचाई करीब 3,095 मीटर से लेकर 6,517 मीटर तक है और यहां तीखी पर्वत श्रृंखलाएं और गहरी घाटियां मौजूद हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक करीब 8.7 किलोमीटर लंबी यह सुरंग चिनाब बेसिन के अतिरिक्त पानी को ब्यास नदी प्रणाली में पहुंचाएगी। इस परियोजना को पाकिस्तान के लिए भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि चिनाब सिंधु जल संधि के तहत पश्चिमी नदियों में शामिल है, जिन पर भारत के अधिकार सीमित रहे हैं। हालांकि, पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने इस संधि को लेकर कड़ा रुख अपना लिया था। पानी मोड़ने का प्रस्तावित स्थल कोस्कर गांव के पास स्थित है और यह अटल टनल रोहतांग के उत्तरी छोर से आगे पड़ता है।

इस परियोजना से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि यह सिर्फ एक इंजीनियरिंग या जलविद्युत परियोजना नहीं है, बल्कि पश्चिमी नदियों के पानी के बेहतर उपयोग की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारतीय नीति निर्माताओं और जल विशेषज्ञों का लंबे समय से मानना है कि पश्चिमी नदियों का काफी पानी पर्याप्त भंडारण और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण बिना इस्तेमाल हुए पाकिस्तान की ओर बह जाता है। चिनाब-ब्यास लिंक परियोजना को इसी समस्या के समाधान के रूप में देखा जा रहा है।

सरकार को उम्मीद है कि इस परियोजना से उत्तर भारत में जलविद्युत उत्पादन की संभावनाएं भी मजबूत होंगी। अधिकारियों के मुताबिक दूसरे चरण में पानी के इस नए प्रवाह का इस्तेमाल बिजली उत्पादन के लिए किया जा सकता है। हिमालयी नदियों को भारत की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा संपत्तियों में गिना जाता है। ऐसे समय में जब देश थर्मल पावर पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है, यह परियोजना ऊर्जा और जल प्रबंधन दोनों दृष्टि से अहम मानी जा रही है।